राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पताः- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेलः-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 03 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-276 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पुतिन के आने से पहले दिल्ली पहुंची रूसी सुरक्षा अधिकारियों की टीम........अंतिम निर्णय और कोर प्रोटोकॉल का संचालन रूसी एजेंसियों के हाथ में

नई दिल्ली । दिल्ली इनदिनों एक अत्यंत संवेदनशील और बहु-स्तरीय सुरक्षा ऑपरेशन का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तैयारियाँ अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पुतिन के आधिकारिक कार्यक्रमों को अत्यंत गोपनीय रखा गया है, किंतु माना जा रहा है कि 4-5 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए रूसी सुरक्षा टीम पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूद है। 50 से अधिक रूसी सुरक्षा अधिकारी पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूसी सुरक्षा दल सिर्फ बाहरी सतह पर नज़र नहीं रख रहे, बल्कि संभावित होटल-स्थलों, एयरपोर्ट के लैंडिंग ज़ोन, आपातकालीन निकासी मार्गों और शहर के संवेदनशील हिस्सों की माइक्रो-प्लानिंग भी कर रहे हैं। एआई-आधारित निगरानी, ड्रोन-डिटेक्शन सिस्टम, स्नाइपर तैनाती और 24म7 कमांड-कंट्रोल रूम की तैयारी ज़ोरों पर है। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एसपीजी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ, रूस की 'इनर रिंग' सुरक्षा टीम के साथ काम कर रही हैं। बता दें कि बाहरी सुरक्षा और लॉजिस्टिक सपोर्ट भारत संभाल रहा है, जबकि अंतिम निर्णय और कोर प्रोटोकॉल का संचालन रूसी एजेंसियों के हाथ में हैं। पुतिन के साथ आने वाला प्रतिनिधिमंडल भी बड़ा और उच्चस्तरीय बताया जा रहा है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल है। उनके लिए विशेष पाक-व्यवस्था, मेडिकल ट्रांसिट सुविधा और अलग-अलग सुरक्षा परतें भी तैयार की जा रही हैं। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में दिल्ली एक इसतरह के 'सिक्योरिटी कवच' में ढँकने जा रही है, जैसा दुनिया के सिर्फ कुछ सबसे शक्तिशाली नेताओं के लिए ही देखा जाता है। नई रणनीतिक उलझनों के बीच होने वाले मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं।

अब नहीं वसूला जाएगा सेटेलाइट से टोल टैक्स, सरकार ने योजना ठंडे बस्ते में डाली

ट्रैकिंग डिवाइस से जासूसी, लोगों की निजता के चलते लिया फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकर की सेटेलाइट से टोल टैक्स वसूलने की योजना अधर में लटक गई है। फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने से जासूसी की आशंका और आम लोगों की निजता से समझौता होने की चिंता के चलते यह कदम उठाया गया है। सरकार भी साफ कर चुकी है कि 1 मई से सैटेलाइट से टोल कलेक्शन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल प्लाजा मुक्त करने और जितनी दूरी, उतना टोल टैक्स के सिद्धांत पर आधारित जीएनएसएस को स्थगित कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इस तकनीक के तहत हर वाहन में ऑन-बोर्ड यूनिट ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य था। इससे वाहन की रूट, स्टॉपेज, गति और गंतव्य जैसी जानकारी रिकॉर्ड होती थी। अधिकारी के मुताबिक इस डाटा के दुरुपयोग से आम नागरिकों के निजी जीवन में दखल और वीआईपी मूवमेंट की जानकारी लीक होने का खतरा था, जो सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा है। सरकार ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और हरियाणा के कुछ हिस्सों में इसका ट्रायल किया था। योजना के मुताबिक हाईवे पर जितनी दूरी गाड़ी तय करेगी, सैटेलाइट के जरिए उतनी ही राशि सीधे बैंक खाते से कट जाती। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह योजना को स्थगित कर दिया गया है। इस तकनीक से वाहन की लोकेशन और वाहन चालक का डाटा ट्रैक किया जाना संभव था। अब मंत्रालय ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन योजना पर काम कर रही है, जिसमें किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। हाईवे पर लगे कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर मौजूदा फास्टैग वॉलेट से ही टोल राशि काट देंगे।

एसआईआर वापस लो और 'प्रधानमंत्री सदन में आओ' के लगे नारे

संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, खड़गे, सोनिया रहे मौजूद

नई दिल्ली।

संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्ष का हमला जारी है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। विपक्षी सांसदों के हाथ में एसआईआर के विरोध में कई पोस्टर भी दिखे, जिनमें इस प्रकिया को रोकने की मांग की है।

विपक्षी दलों के संसद भवन में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, द्रमुक नेता टीआर बालू और कई अन्य विपक्षी सांसद भी मौजूद थे। प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं ने एसआईआर वापस लो और 'प्रधानमंत्री सदन में आओ' के नारे लगाए। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उनका यह प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। जो अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे।

इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को भी विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया था। सरकार ने कहा कि वह चर्चा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समययीमा तय नहीं की जा सकती। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव सुधारों पर चर्चा के खिलाफ नहीं है

लेकिन सरकार जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। रिजिजू ने कहा कि सरकार एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर विचार कर रही है और इस मांग को खारिज नहीं किया गया है।

पीएम मोदी बोलते हैं..........तब दुनिया भर के नेता ध्यान से सुनते, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत

पुणे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर संघ प्रमुख ने कहा

पुणे ।

आरएसएस की स्थापना के सौ साल पूरे होने के मौके पर में पुणे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोलते हैं, तब विश्व के नेता ध्यान से सुनते हैं। इसका मुख्य कारण भारत की ताकत सामने आ रही है और देश को उसका उचित स्थान मिल रहा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर इतने ध्यान से इसलिए सुना जा रहा है, क्योंकि भारत की शक्ति अब उन जगहों पर दिखने लगी है, जहां भारत को उचित रूप से प्रकट होना चाहिए, और इसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर, उन्होंने जोर दिया कि किसी को केवल जश्न मनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दिए गए कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ ने चुनौतियों और तूफानों से जूझते हुए 100 साल पूरे किए हैं, लेकिन अब आत्मचिंतन का समय है कि पूरे समाज को एकजुट करने के काम में इतना समय क्यों लगा।

भारत का महत्व और वैश्विक शांति- आमतौर पर यह माना जाता है कि जब भारत आगे बढ़ता है, तो वैश्विक समस्याएं हल हो जाती हैं, संघर्ष कम हो जाते हैं और शांति कायम होती है। उन्होंने कहा कि यह बात इतिहास में दर्ज है और हमें इसे फिर से साकार करना होगा, क्योंकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां भारत से इसकी मांग करती हैं। उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के बलिदानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने कई बाधाओं और चुनौतियों के बीच अपना मिशन शुरू किया था, और उन्होंने सफलता के बीज बोए और अपना जीवन समर्पित करके परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। भागवत ने कहा कि जब संघ संवाद और सामूहिक कार्य की ताकत की बात करता है, तो इसका तात्पर्य

पूरे समाज से होता है। उन्होंने जोर दिया कि संघ की नींव विविधता में एकता में निहित है, और सभी को साथ मिलकर चलना होगा, जिसके लिए धर्म आवश्यक है। उनका मानना है कि भारत में सभी दर्शन एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, और चूंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें सद्भाव के साथ आगे बढ़ना होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले- लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध-प्रदर्शन ज़रूरी

सदन में 'वोट चोर-गद्दी छोड़' के लगे नारे, कुछ सांसद वेल तक पहुंचे

नई दिल्ली।

लोकसभा में एसआईआर को लेकर विपक्ष का असंतोष दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्यवाही जैसे ही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में 'वोट चोर-गद्दी छोड़' के नारे गूंजे और कुछ सांसद सीधे वेल में जा पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने शांति बनाए रखते हुए प्रश्नकाल जारी रखा, लेकिन विपक्ष की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 20 मिनट बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर, राज्यसभा में भी कमोबेश वही दृश्य- नारेबाजी, पोस्टर और एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध-प्रदर्शन ज़रूरी है। विपक्ष सुबह 10-30 बजे संसद परिसर के मकर द्वार के सामने भी जुटा और एसआईआर पर तुरंत चर्चा की मांग दोहराई। सत्र के पहले दिन से ही एसआईआर, वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता को लेकर विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में साफ कहा था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, बस विपक्ष इस पर कोई टाइमलाइन न तय करे। सूत्रों की मानें तो विपक्ष इतना भी नहीं कह रहा कि एसआईआर शब्द ही रहना चाहिए। सरकार चाहे तो इसे इलेक्शन रिफार्म, चुनावी सुधार या किसी भी नाम से सूचीबद्ध कर सकती है। सरकार इस सुझाव पर सकारात्मक दिख रही है और बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में अपना रुख रख सकती है। इसी बीच सरकार संसद में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर 10 घंटे की विशेष चर्चा कराने पर विचार कर रही है। संभावना है कि पीएम मोदी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह प्रस्ताव 30 सितंबर को राज्यसभा की बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में आया था। हांलाकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री आवास के बाद पीएमओ का नाम बदलकर........सेवातीर्थ किया गया

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलने के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नाम बदलकर अब सेवातीर्थ किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) जल्द ही साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होगा। यह बड़ा बदलाव दशकों बाद हो रहा है। नया पीएमओ सेवा तीर्थ-1 से काम करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में बनी तीन नई आधुनिक इमारतों में से एक है।

इस कॉम्प्लेक्स की सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3 इमारतों में कैबिनेट सेक्रेटेरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) का ऑफिस होगा। इसकी शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेवा तीर्थ-2 में एक अहम मीटिंग की थी। यह नया कॉम्प्लेक्स सरकारी कामकाज को और तेज बनाएगा और भारत सरकार के काम करने के तरीके में एक नया अध्याय लिखेगा।

यह नया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स वायु भवन के पास एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में बनाया गया है। इसमें तीन शानदार इमारतें हैं। इसमें से पहली इमारत, सेवा तीर्थ-

1, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नया घर बनेगी। यह साउथ ब्लॉक से दशकों बाद हो रहा एक बड़ा बदलाव है।

बाकी दो इमारतें, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3, भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का दफ्तर होगा। यह वहीं जगह है जहां सरकार के बड़े फैसले होते हैं। सेवा तीर्थ-3 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) का ऑफिस होगा। एनएसए देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मामलों को देखते हैं।

यह शिफ्टिंग का काम अब शुरू हो गया है। यह नया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां सब कुछ हाई-टेक होगा। इससे सरकारी कामकाज में और तेजी लाएगा। यानी, फाइलें जल्दी निपटेंगी और फैसले भी तेजी होने है।

तिब्बत में फिर आया 3.3 तीव्रता का भूकंप

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के बयान में कहा गया है कि मंगलवार को तिब्बत में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 5 किमी की उथली गहराई पर आया, जिससे यह आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील है। इसके पहले सोमवार को, 50 किमी की गहराई पर 3.3 तीव्रता का एक और भूकंप आया था। बात दें कि उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुँचने की दूरी कम होती है, जिसके ज़मीन ज़्यादा हिलती है और ज्यादा नुकसान की संभावना होती है। तिब्बती पठार टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण होने वाली भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तिब्बत और नेपाल एक प्रमुख भूगर्भीय भ्रंश रेखा पर मौजूद हैं, जहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और इसके परिणामस्वरूप भूकंप आना सामान्य घटना है। यह क्षेत्र टेक्टोनिक उत्थान के कारण भूकंपीय रूप से सक्रिय है जो हिमालय की चोटियों की ऊँचाई को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है।

एलन मस्क ने किया बड़ा दांव............2030 तक दुनिया में होगा वैश्विक परमाणु युद्ध

वाशिंगटन । टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने फिर अपने विवादित बयान से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने खुलकर दावा किया कि दुनिया जल्द ही एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रही है। दरअसल, एक यूजर ने लिखा कि न्यूक्लियर हथियारों के कारण बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध नहीं हो रहे, इससे सरकारों का ध्यान शासन से हट गया है।

इस पर मस्क ने चौंकाने वाला जवाब दिया ÷वार इस इनएविटेबज. 5 साल, 10 एट मस्ट, यानि (युद्ध अवश्यंभावी है। 5 साल में, 2030 तक या अधिकतम 10 साल 2040 में।) मस्क के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उन्होंने नहीं बताया कि कौन-सा युद्ध, किन देशों के बीच या किस वजह से होगा। लेकिन मस्क का साफ इशारा इस बात की ओर था कि दुनिया धीरे-धीरे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है।

वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बयान की व्याख्या जानने के लिए मस्क की एआई-ग्रोक से सवाल पूछे। ग्रोक ने मस्क के पुराने बयानों का हवाला देकर कहा कि मस्क कई संभावित खतरों की चेतावनी पहले भी दे चुके हैं। बात दें कि यूरोप और ब्रिटेन में संभावित गृहयुद्ध, बढ़ते प्रवास और पहचान राजनीति के कारण हो सकता है। वहीं आने वाले सालों में अमेरिका-चीन के बीच ताइवान को लेकर युद्ध की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में चल रहे यूक्रेन-रूस संघर्ष के तीसरी जंग में बदलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यानी, मस्क के अनुमान के अनुसार आने वाले वर्षों में दुनिया के कई हॉटस्पॉट तनाव को युद्ध में बदल सकते हैं।

लापरवाह एम वाय अस्पतालः लगाने वाला इंजेक्शन मरीज को पिला दिया, हुई मौत

- चूहा कांड के बाद नेशनल प्लेयर को एक्सपायर स्लाइन चढ़ाने के बाद प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एक और गैर जिम्मेदार कारनामा

इन्दौर .

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इन्दौर के एम वाय में लगातार हो रही लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से मरीजों की जिंदगी मौत बन रही है। बड़े विश्वास से परिजन बीमार को लेकर यहां आते है और मुर्दा लाश या एक नई बीमारी साथ लें जाने को मजबूर हो जाते हैं। और एम वाय में शुरू हो जाती है जांच के नाम पर शासन प्रशासन की नौटंकी। विगत दिनों चूहों के काटने से नवजात की मौतों, फिर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को एक्सपायरी डेट की स्लाइन लगाने के मामले सामने आने के बाद अब एक और ऐसा ही लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का मामला एम वाय में सामने आया है जिसमें पैंतीस वर्षीय बलवीर की मौत के बाद उसके परिजन ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलबीर को उसके परिजन देवास में हुए सड़क हादसे में घायल होने के बाद गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लेकर आए थे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है उनका कहना है कि आईवी इंजेक्शन जिसे मरीज को लगाया जाना था, उस इंजेक्शन को उसे मुंह से पिला दिया गया, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में एम वाय के कैजुअल्टी प्रभारी डॉ. परेश सोंधिया का कहना है कि देवास से आए मरीज का समय पर इलाज शुरू कर दिया गया मुंह से इंजेक्शन पिलाने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे वेंटीलेटर भी उपलब्ध करवाया गया था। मामले में नोटिस जारी कर घटना से संबंधित जानकारी मांगी है। वहीं मृतक के परिजन अंकित परिहार के अनुसार पूरा मामला इस प्रकार है कि रविवार रात 10-30 बजे घायल अवस्था में बलवीर को एंबुलेंस से इंदौर एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जब यहां पहुंचे तो कैजुअल्टी में ना डॉक्टर मिला, ना वार्डबॉय और ना ही कोई सपोर्टिंग स्टॉफ। तीन घंटे तक मरीज को भर्ती नहीं किया गया। अटेंडर बार-बार डॉक्टरों को बुलाते रहा, लेकिन कोई नहीं आया। रातभर सिर्फ एक अनुभवहीन ट्रेनिंग डॉक्टर ही मरीज को देखते रहा, वह भी बिना इलाज किए। सबसे चौंकाने वाली बात तो

सुबह हुई जब न्यूरो सर्जरी विभाग से एक डॉक्टर नींद के झोंक की हालत में आया और मरीज को इंजेक्शन लगाने के बजाए पिला दिया। इसके बाद भी जब मरीज की हालत बिगड़ती रही तो डॉक्टर इलाज करने की बजाय मशीनों के ग्राफ का वीडियो बनाते रहे। परिजनों का आरोप है कि यह मौत नहीं, बल्कि अस्पताल की लापरवाही से हुआ कत्ल है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सदन बनाम शोर,शीतकालीन सत्र की पहली भोर में राजनीतिक टकराव और संवाद की नयी चुनौती

सत्र की शुरुआत में सी.पी. राधाकृष्णन को राज्यसभा के नए सभापति के रूप में स्वागत किया गया। मोदी ने उनके अनुभव की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही अधिक गरिमामय और प्रभावी होगी। लेकिन स्वागत समारोह के माहौल में भी दलगत राजनीति की तल्खी कम नहीं हुई।

(लेखक – कांतिलाल मांडोत)

शीतकालीन सत्र हमेशा से राजनीतिक तापमान का आईना माना जाता रहा है। वर्ष के अंतिम महीने में जब केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तब विपक्ष इसे जवाबदेही और जनहित के मुद्दों को उठाने के अवसर के रूप में देखता है। इसी उम्मीद और उत्सुकता के बीच 1 दिसंबर से आरंभ हुआ संसद का यह शीतकालीन सत्र, अपने पहले ही दिन उस सौहार्द और गंभीरता से दूर दिखाई दिया जिसकी एक लोकतांत्रिक संस्था से अपेक्षा की जाती है।पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कारण वही पुराना–हंगामा, नारेबाजी और तीखी राजनीतिक तल्खी। सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि संसद का मंच राजनीति की लड़ाई का एरिना नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर काम करने का स्थान है। उनकी टिप्पणी, सदन में ड्रामा नहीं, डिलेवरी चाहिए, में सिर्फ राजनीतिक व्यंग्य नहीं था, बल्कि कार्यसंस्कृति पर गंभीर चिंता का संकेत भी झलक रहा था।मोदी ने विपक्ष से यह भी कहा कि चुनाव परिणामों में पराजय मिलना राजनीतिक जीवन का अंग है, लेकिन पराजय की निराशा में डूबकर सदन को ठप कर देना लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार ट्रिप्स जैसी बहसों और विधायी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी संभव है जब विपक्ष मजबूत मुद्दे उठाए और सहयोग की भावना दिखाए। अचानक इस्तीफे पर राजनीति का बवंडर तेज हुआ।सत्र की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा राजनीतिक तूफ़ान उस वक्त खड़ा हो गया जब राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जैसे पदों को संभाल चुके धनखड़ के इस निर्णय ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे असामान्य कदम बताते हुए सवाल किया कि इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ने के पीछे कौन–सा दबाव या परिस्थिति रही होगी।

खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर खड़गे जी को इस विषय में बहुत तकलीफ हो रही है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह बयान दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच वाद–विवाद कैसे मोड़ ले सकता है।सत्र का एजेंडा बड़ा, लेकिन माहौल गर्म है।शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होना है। कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और सरकार लगभग 10 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें तंबाकू और पान मसाला पर सेस लगाने वाला बिल, दिवाला कानून में सुधार, और जनविश्वास संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव शामिल हैं। संसदीय समितियों को भी कई रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इससे सरकार के विधायी कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडराते नजर आए। सरकार का आरोप है कि विपक्ष बिना पर्याप्त चर्चा के सिर्फ बाधा उत्पन्न करने की रणनीति अपना रहा है। वहीं विपक्ष कहता है कि उसके सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा और सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में हो रहे व्यवधानों पर स्पष्ट अपील की।मेरी चिंता यह है कि सदन चले। जनता हम सब से काम की उम्मीद करती है।

नए सभापति का स्वागत और पुरानी राजनीति की छाया

सत्र की शुरुआत में सी.पी. राधाकृष्णन को राज्यसभा के नए सभापति के रूप में स्वागत किया गया। मोदी ने उनके अनुभव की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही अधिक गरिमामय और प्रभावी होगी। लेकिन स्वागत समारोह के माहौल में भी दलगत राजनीति की तल्खी कम नहीं हुई।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के लिए अनुचित शब्द बोले। यह आरोप भी सत्र के शुरुआत में तनाव का एक और सूत्र बन गया।

विपक्ष के भीतर भी समानता नही लेकिन भिन्न आवाजेंसुनाई दी।हंगामे के इस माहौल में विपक्ष के भीतर भी अलग–अलग स्वर सुनाई दिए। गोगोई ने कहा कि अगर विपक्ष के मुद्दों को सत्र में उचित स्थान और चर्चा मिले, तो वे सरकार के सभी विधेयकों पर सहयोग करने को तैयार हैं। यह बयान संकेत देता है कि विपक्ष की मंशा केवल हंगामा करना नहीं है, बल्कि बहस और संवाद भी चाहता है।यदि उसे सम्मानजनक अवसर मिले।

हालाँकि, इस बीच राहुल गांधी सदन से उस समय बाहर निकल गए जब कार्यवाही हंगामे के कारण रुकावट का सामना कर रही थी। यह घटना भी राजनीतिक व्याख्याओं का विषय बनी।इस बीच चिराग पासवान ने कहा कि हंगामा छवि चमकाता है, काम नहीं,लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने विपक्ष के विरोध को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।हंगामा करने वाला अपनी छवि चमकाता है, लेकिन काम नहीं करता। पासवान के इस वक्तव्य ने सत्ता पक्ष की उस भावना को मजबूत किया, जिसमें वे कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है और संसद के संचालन में बाधा डाल रहा है।

हंगामा बनाम लोकतंत्र

सत्र के पहले दिन जिस प्रकार कार्यवाही बाधित हुई, उसने इस विवाद को फिर जन्म दिया कि क्या लगातार हंगामे के माध्यम से विपक्ष अपनी भूमिका को कमजोर कर रहा है, या यह उनके लिए मजबूरी है क्योंकि सरकार उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं देती?सत्ता पक्ष का तर्क है कि हंगामा लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। संसद बहस, विचार और नीतिगत विमर्श का स्थान है, और लगातार व्यवधान से न सिर्फ विधायी कामकाज रुकता है, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगाता है।विपक्ष का दावा है कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की चुप्पीऔर अड़ियल रवैया उन्हें कठोर कदम उठाने पर मजबूर करता है।लोकतंत्र का बड़ा सवाल है किसदन में पहले दिन की उथल–पुथल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र किसी राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं होगा। सरकार जहां विकास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर विधायी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष अधिक आक्रामक और तप्त सवालों के साथ तैयार बैठा है।

इस सत्र की असली कसौटी यह होगी कि क्या संसद अपने मूल दायित्व जनता के लिए कानून बनाना और शासन पर निगरानी रखना,को पूरा कर पाएगी या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण इसे फिर से जाम कर देगा?

लोकतंत्र का सार संवाद है, और संवाद के लिए बहस काअधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संयम का। पहले दिन की घटनाओं ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा राजनीतिक वर्ग इस संतुलन को पुनः स्थापित कर पाएगा।

शीतकालीन सत्र की यह आरंभिक हलचल संकेत देती है कि आने वाले 18 दिन शांत नहीं रहने वाले। परंतु यदि सत्ता और विपक्ष अपने–अपने राजनीतिक हितों के ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें, तो यह सत्र महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दे सकता है।अंततः संसद जनता की उम्मीदों का मंच है। और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए चाहिए न ड्रामा, न आरोपों का तूफान,बल्कि ठोस कार्य, सार्थक बहस और लोकतांत्रिक परिपक्वता। यह तभी सम्भव है,जब विपक्ष इस बात को समझे और समझकर उनकी जवाबदेही पर पुनः विचार करे।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

एसआईआर के सवाल

निस्संदेह, किसी लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है ताकि वाजिब वोट ही चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाए। इसी आलोक में नौ राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल तार्किक समाधान मांगते हैं। इस प्रक्रिया में तुरत–फुरत की कार्यनीति के चलते कई राज्यों में अफरा–तफरी का आलम नजर आता है। जिसका दबाव जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक–तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय–सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है। निस्संदेह, स्वतंत्र–निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि उनके नाम सूचियों में सही ढंग से दर्ज हो सकें। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ–स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। यदि एसआईआर की प्रक्रिया किसी विवाद में उलझी रहती है तो इस अभियान का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के घटनाक्रमों से मिले सबक को अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान याद रखा जाना चाहिए। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान–निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है। उल्लेखनीय है कि जहां बीएलओ पर कार्यदबाव व समय सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों का आरोप है कि अतिरिक्त कार्य–दबाव का उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है।

41 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है गैस त्रासदी का असर

(लेखक –– योगेश कुमार गोयल / ईएमएस)

– भोपाल गैस त्रासदी से निकलते जहरीले सवाल

(भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी (3 दिसम्बर) पर विशेष)

1984 में 2–3 दिसम्बर की रात भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया था, जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। भयानक गैस त्रासदी की उस घटना को पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी और हृदयविदारक औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 2–3 दिसम्बर 1984 को आधी रात के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से निकली जहरीली गैस 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' ने हजारों लोगों की जान ली थी। उस जानलेवा त्रासदी से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। दुर्घटना के चंद घंटों के भीतर ही कई हजार लोग मारे गए थे और मौतों का यह दिल दहलाने वाला सिलसिला उस रात से शुरू होकर कई वर्षों तक अनवरत चलता रहा। हालांकि इसी साल भोपाल के जहरीले कचरे का निपटान किया जा चुका है किन्तु भोपाल गैस कांड को 41 साल बीत जाने के बाद भी इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इस त्रासदी से पीड़ित होने वालों के जख्म आज भी हरे हैं। भोपाल गैस त्रासदी पत्थर दिल इंसान को भी इस कदर विचलित कर देने वाली थी कि हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था जबकि करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा था, आसपास के सभी पेड़ बंजर हो गए थे। एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से हजारों लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और जो जिंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी पल–पल मरने को विवश हैं। इनमें से बहुत से लोग कैंसर सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और घटना के 40 साल बाद भी इस गैस त्रासदी के दुष्प्रभाव खत्म नहीं हुए हैं। विषैली गैस के सम्पर्क में आने वाले लोगों के परिवारों में इतने वर्षों बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे जन्म ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैस त्रासदी से 3787 की मौत हुई और गैस से करीब 558125 लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि कई एनजीओ का दावा रहा है कि मौत का यह आंकड़ा 10 से 15 हजार के बीच था तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक करीब 8 हजार लोगों की मौत तो दो सप्ताह के भीतर ही हो गई थी जबकि करीब 8 हजार अन्य लोग रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों के चलते मारे गए थे।

हजारों लोगों के लिए काल बने और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले भोपाल में यूसीआईएल के कारखाने का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था, जहां 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' (मिक) नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला गया लेकिन भोपाल गैस त्रासदी की घटना के समय तक उस कारखाने में सुरक्षा उपकरण ठीक हालात में नहीं थे और वहां सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। उस कारखाने के टैंक संख्या 610 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी और गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री था। पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा बिजली का बिल बचाने के लिए मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। 3 दिसम्बर 1984 को इस कार्बाइड फैक्टरी से करीब 40 टन गैस का जो रिसाव हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ पानी मिल जाने से रासायनिक प्रक्रिया होने के परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया था और यह जहरीली गैस देखते ही देखते पूरे वायुमंडल में फैल गई। अचानक हुए जहरीली गैस के इस रिसाव से बने गैस के बादल हवा के झोंके के साथ वातावरण में फैल गए और इसकी चपेट में आने वाले लोग मौत की नींद सोते गए।

जिन लोगों के फेफड़ों में सांस के जरिये गैस की ज्यादा मात्रा पहुंच गई, वे सुबह देखने के लिए जीवित ही नहीं बचे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जिन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है? दुर्घटना के चार दिनों बाद 7 दिसम्बर 1984 को यूसीआईएल अध्यक्ष एवं सीईओ वारेन एंडर्सन की गिरफ्तारी हुई थी किन्तु विड़म्बना देखिये कि इतने भयानक हादसे के मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के महज छह घंटे बाद मात्र 2100 डॉलर के मामूली जुर्माने पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद वह अवसर का लाभ उठाते हुए भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका भाग गया, जिसे भारत लाकर सजा देने की मांग निरन्तर उठती रही लेकिन भारत सरकार अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण कराने में विफल रही। 29 सितम्बर 2014 को वारेन एंडर्सन की मौत हो गई। इस हादसे से पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंची, जिसकी भरपाई सरकारें आज तक नहीं कर पाई हैं। सरकारों का रूख इस पूरे मामले में संवेदनहीन ही रहा। कई रिपोर्टों में इस क्षेत्र में भूजल प्रदूषण की पुष्टि होने के बाद भी सरकार द्वारा जमीन में दफन जहरीले कचरे के निष्पादन की कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। दरअसल इस भयावह गैस त्रासदी के बाद हजारों टन खतरनाक अपशिष्ट भूमिगत दफनाया गया था और सरकारों ने भी स्वीकार किया है कि यह क्षेत्र दूषित है। गैस रिसाव के करीब आठ घंटे बाद भोपाल को भले ही जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था किन्तु हकीकत यही है कि इस गैस त्रासदी के 41 वर्षों बाद भी भोपाल उस हादसे से उबर नहीं पाया है।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

गुरु का पाठ

गंगा के किनारे बने एक आश्रम में महर्षि मुद्गल अपने अनेक शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उन दिनों वहां मात्र दो शिष्य अध्ययन कर रहे थे। दोनों काफी परिश्रमी थे। वे गुरु का बहुत आदर करते थे। महर्षि उनके प्रति समान रूप से स्नेह रखते थे। आखिर वह समय भी आया, जब दोनों अपने–अपने विषय के पारंगत विद्वान बन गए। मगर इस कारण दोनों में अहंकार आ गया। वे स्वयं को एक–दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगे। एक दिन महर्षि स्नान कर पहुंचे तो देखा कि अभी आश्रम की सफाई भी नहीं हुई है और दोनों शिष्य सोकर भी नहीं उठे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। महर्षि ने जब दोनों को जगाकर सफाई करने को कहा तो दोनों एक–दूसरे को सफाई का आदेश देने लगे। एक बोला–मैं पूर्ण विद्वान हूं। सफाई करना मेरा काम नहीं है। इस पर दूसरे ने जवाब दिया–मैं अपने विषय का विशेषज्ञ हूं। मुझे भी यह सब शोभा नहीं देता। महर्षि दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा– ठीक कह रहे हो तुम लोग। तुम दोनों बहुत बड़े विद्वान हो और श्रेष्ठ भी। यह कार्य तुम दोनों के लिए उचित नहीं है। यह कार्य मेरे लिए ही ठीक है। उन्होंने झाड़ू उठाया और सफाई करने लगे। यह देखते ही दोनों शिष्य मारे शर्म के पानी–पानी हो गए। गुरु की विनम्रता के आगे उनका अहंकार पिघल गया। उनमें से एक ने आकर गुरु से झाड़ू ले लिया और दूसरा भी उसके साथ सफाई के काम में जुट गया। उस दिन से उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया।

विचार मंथन

मोबाइल फोन पर अब निजता का अधिकार?

(लेखक – सनत जैन)

तेजी से डिजिटल होती दुनिया में मोबाइल फोन अब केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की निजी जरुरत बन चुका है। इसी वजह से फोन से जुड़ी किसी भी सरकारी नीति को लेकर नागरिकों की चिंता स्वाभाविक है। विशेषकर तब, जब सरकार की दूरसंचार नीति सीधे तौर पर लोगों के व्यक्तिगत डेटा, लोकेशन, गैलरी या संदेशों, उनकी पसंद ना पसंद और निजी संबंधों तक की पहुंच पर प्रश्न खड़ा करती हो। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक एवं सभ्य समाज की आत्मा है। निजता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है। नागरिक अपनी व्यक्तिगत जानकारी, गतिविधियों और संचार पर नियंत्रण रखने का अधिकार रखते हैं। जब किसी सरकारी ऐप को अनिवार्य रूप से फोन में इंस्टॉल करने की बात सामने आती है। वह भी बिना हटाने के विकल्प के साथ तो सरकार की यह कार्यवाही सीधे लोगों के निजी अधिकार के साथ–साथ उनकी स्वतंत्रता को भी बाधित करती है। सरकार का यह निर्णय सीधे सवालों के घेरे में आ जाता है। विपक्ष के बढ़ते दबाव और विरोध के बीच सरकार को कहना पड़ा है, कि इसे फोन में रखना जरूरी नहीं है। इस ऐप को यूजर डिलीट भी कर सकते हैं। ऐप पद विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी है।

बहरहाल सरकारी ऐप को लेकर अब नागरिकों को लगने लगा है, सरकार नागरिकों की पल–पल की जासूसी करके बंधुआ बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है, ये सरकारी ऐप साइबर सुरक्षा को मजबूत करेंगे। चोरी, साईबर फ्रॉड को रोकने और मोबाइल के सभी संव्यवहार को सुरक्षित बनाएंगे। निःस्संदेह, उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। दरअसल साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। नागरिकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी भी है। तकनीकी को लागू करने के पूर्व सरकार को उस नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, नागरिकों को उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। भारत में तकनीकी को पहले लाया जाता है, उसके बाद सुरक्षा और खतरों को लेकर सरकार सजग होती है। जिसके कारण नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सुरक्षा का नाम लेकर सरकार द्वारा अनिवार्य निगरानी प्रणाली स्थापित करना कितना उचित है। यह गंभीर बहस एवं चिंता का विषय बन गया है। सुरक्षा और निगरानी, दोनों के बीच की दीवार बेहद पतली है। यदि किसी ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, गैलरी और एसएमएस तक स्थायी पहुंच सतत मिलती है, तो यह केवल सुरक्षा नहीं, वरन व्यापक नियंत्रण का साधन बन सकता है। लोकतंत्र में राज्य को नागरिकों पर इतनी व्यापक दृष्टि रखने की अनुमति देने से पहले पारदर्शिता, सामाजिक सहमति और मजबूत कानूनी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिकों के पास स्वयं यह अधिकार होना चाहिए, कि जो व्यक्ति चाहे इस ऐप को इंस्टॉल करे, ना चाहे तो ना करे।

यह स्वतंत्रता उसकी निजता का हिस्सा और एक संवैधानिक अधिकार भी है। सरकार की नीतियां नागरिकों के भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए, भय अथवा शक का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। आधुनिक तकनीक का उद्देश्य जनता को सशक्त बनाना है। नाकि उनकी निजी ज़िंदगी में अनियंत्रित हस्तक्षेप का साधन बने। सुरक्षा के नाम पर निजता का हनन अब सामान्य बात हो गई है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी कमजोर होती चली जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मोबाइल सुरक्षा के बहाने नागरिक अपनी निजता की अंतिम दीवार को गिरने देंगे? यदि ऐसा हो गया तो परिवार और निजी संबंध जिसमें सामाजिक आर्थिक और अन्य गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में होंगी। ऐसी स्थिति में हमारी स्वतंत्रता खतरे में पडना तय है। इसे लेकर नागरिकों में एक अनजाना भय व्याप्त होने लगा है, जिसके चलते आक्रोष भी पनपने लगा है। दरअसल नागरिकों को लग रहा, सरकार जिस तरह से हमारे ऊपर नियम–कानून लागू करना चाहेगी, जैसे भी रखना चाहेगी, उसका हम कभी पूरी तरह से विरोध भी नहीं कर पाएंगे और सरकार के ऊपर निर्भर होकर रह जाएंगे। लोकतंत्र में नागरिकों की जागरूकता ही वास्तविक नागरिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार की शक्ति है। इसे बनाए रखने के लिए सभी को सजग रहने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने की रिलायंस और अधिकारियों की याचिका खारिज

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके दो अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। याचिका प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सेट) के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजार को तुरंत स्पष्टीकरण न देने पर सेबी का 30 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया था। सेबी ने पाया कि आरआईएल और उसके अधिकारी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) का तत्काल खुलासा करने में विफल रहे। जुर्माने का निर्णय जून 2022 में लिया गया था और सेट ने इसे दो मई 2025 को बरकरार रखा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सेट के निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं और इसमें कोई कानूनी सवाल नहीं है।

दिल्ली-मुंबई एयरपोर्ट में सफर करना हो सकता है महंगा

- विवादित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली । दिल्ली के इंदिरा गांधी और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर यात्रियों से वसूले जाने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस (यूडीएफ) में भारी वृद्धि हो सकती है। यह टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) के हालिया आदेश के कारण सामने आया है, जिसमें 2009-2014 के एयरलाइन टैरिफ की गणना का फॉर्मूला दोबारा तय किया गया है। दिल्ली में घरेलू यात्रियों के लिए यूडीएफ 129 रुपए से बढ़कर 1,261 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 650 से 6,356 रुपए तक हो सकता है। मुंबई में घरेलू यात्रियों के लिए यह 175 से 3,856 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 615 से 13,495 रुपए तक पहुंच सकता है। भारतीय और विदेशी एयरलाइंस ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

रिलायंस ने स्टार इंडिया का जियोस्टार में विलय पूरा किया

- संयुक्त कंपनी का मूल्य लगभग 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर

नई दिल्ली । रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी अनुषंगी कंपनी स्टार टेलीविजन प्रोडक्शंस लिमिटेड (एसटीपीएल) का जियोस्टार के साथ विलय पूरी कर ली है। एसटीपीएल 'स्टार' ब्रांड की मालिक है और समूह कंपनियों को इसे लाइसेंस देती है। रिलायंस ने 14 नवंबर 2024 को इस विलय योजना की जानकारी दी थी। जियोस्टार ने 30 नवंबर 2025 को सूचना दी कि विलय अब प्रभावी हो गया है। जियोस्टार, रिलायंस के मीडिया कारोबार और वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार के विलय के बाद बनी संयुक्त कंपनी है। संयुक्त कंपनी का मूल्य लगभग 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है। यह भारत का प्रमुख मीडिया और मनोरंजन मंच बन चुका है। जुलाई-सितंबर तिमाही में जियोस्टार ने 7,232 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,322 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। फरवरी में जियोसिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का विलय कर नया ओटीटी प्लेटफॉर्म 'जियोहॉटस्टार' लॉन्च किया गया था। इस विलय से रिलायंस मीडिया कारोबार को और मजबूत और व्यापक टीवी व ओटीटी प्लेटफॉर्म का नेतृत्व हासिल होगा।

सरकार का बड़ा फैसला: सभी नए स्मार्टफोनों में 'संचार साथी' ऐप अनिवार्य

- 'संचार साथी' ऐप उपयोगकर्ताओं द्वारा हटाया नहीं जा सकेगा

नई दिल्ली ।

भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब देश में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में 'संचार साथी साइबर सेफ्टी ऐप' पहले से इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा। साथ ही इसे यूज़र द्वारा हटाया नहीं जा सकेगा। जो फोन पहले से सप्लाई चेन में हैं, उनके लिए यह ऐप सॉफ़्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि साइबर धोखाधड़ी, फोन चोरी, सिम कार्ड के दुरुपयोग और अन्य साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। 'संचार साथी' ऐप इन जोखिमों से सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। इसे अनिवार्य बनाकर हर यूज़र इसके सुरक्षा फीचर्स का लाभ उठा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम फोन निर्माता कंपनियों की प्रीलोडेड ऐप पॉलिसी, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन और डेटा सुरक्षा अनुपालन पर असर डाल सकता है। कंपनियों को अपने सिस्टम अपडेट और फ्रेमवर्क में बदलाव करना होगा। चूंकि ऐप हटाया नहीं जा सकेगा, कई यूज़र्स इसे

बाध्यकारी ऐप के रूप में देख सकते हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । अमेरिक डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 41 पैसे की गिरावट के साथ ही 89.94 पर बंद हुआ। इससे पहले सुबह विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की व्यापक मजबूती और लगातार विदेशी पूंजी की

निकासी के बीच रुपया शुरुआती कारोबार में 32 पैसे टूटकर 89.85 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार कंपनियों, आयातकों और विदेशी निवेशकों द्वारा डॉलर की मजबूत मांग ने रुपये पर अतिरिक्त दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.70 पर खुला था, जो जल्दी ही नए निचले स्तर पर फिसल गया। सोमवार को यह 89.79 प्रति डॉलर तक गिरने के बाद 89.53 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 99.41 पर स्थिर दिखा।

टाटा स्टील का पोर्ट टैलबॉट प्लांट में बड़ा बदलाव, आय प्रभा वित

- टाटा स्टील की पुरानी भट्टी बंद कर नई इलेक्ट्रिक भट्टी लगाने की तैयारी

नई दिल्ली ।

टाटा स्टील का पोर्ट टैलबॉट प्लांट सितंबर 2024 में अपनी आखिरी पारंपरिक भट्टी बंद कर चुका है। इसके स्थान पर कंपनी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) लगा रही है, जो बिजली से चलेगी और कम प्रदूषण करेगी। इस नई भट्टी की कुल लागत 1.25 बिलियन पाउंड है, जिसमें से 500 मिलियन पाउंड सरकार दे रही है। नया प्लांट 2027 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। जब तक नया प्लांट नहीं बनता, टाटा स्टील यूके दूसरे देशों से स्टील स्लैब मंगाकर काम चला रही है। इससे लॉजिस्टिक व्यवस्था कठिन हो गई है और उत्पादन खर्च बढ़ गया है। वहीं वैश्विक बाजार में स्टील की कीमतें गिरने से कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ा है। कंपनी पिछले साल 200 मिलियन पाउंड बचा चुकी थी और इस साल भी उतना ही बचाने की योजना है। कुल तय लागत में से लगभग 40 फीसद की कटौती की गई है। कर्मचारियों की संख्या कम की गई, कई कॉन्ट्रेक्ट दोबारा किए गए और दफ्तर में खर्च पर रोक लगाई गई है। फिर भी, बाजार की कमजोरी के कारण ये बचत पूरी तरह लाभकारी नहीं हो रही। ब्रिटेन में फ्लैट स्टील की मांग 2018 से 33 फीसद कम हो गई है, जबकि आयात की सीमा 20 फीसदी बढ़ गई है। इससे विदेशी सस्ता स्टील बाजार में भर गया और घरेलू कीमतें गिर गईं। टाटा स्टील का कहना है कि अगर सरकार यूरोप जैसी कठोर आयात नीतियां अपनाए, तो उद्योग की स्थिति जल्दी सुधर सकती है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 503, निफ्टी 143 अंक गिरा

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवारा को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी रहने से आई है। आज दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 503.63 अंकों टूटकर 85,138.27 अंकों पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 143.55 अंक नीचे आकर 26,032.20 अंकों पर बंद हुआ। आज बैंकिंग स्टॉक्स सहित सेंसेक्स और निफ्टी की ज्यादातर कंपनियों के शेयर नीचे आये थे। वहीं गत दिवस भी बाजार हल्की गिरावट पर बंद हुआ था।

आज सेंसेक्स की 30 में से केवल 10 कंपनियों के शेयर भी तेजी के साथ में बंद हुए और शेष सभी 20 कंपनियों के शेयर गिरावट पर बंद हुए। इसी तरह निफ्टी की 50 में से केवल 15 कंपनियों के शेयर ही बढ़त पर बंद हुए और शेष सभी 35 कंपनियों के शेयर गिरे। आज सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल एशियन पेंट्स के शेयर सबसे ज्यादा 3.17 फीसदी बढ़कर बंद हुए जबकि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर आज सबसे ज्यादा 1.14 फीसदी नीचे आकर बंद हुए।

इनके अलावा, आज सेंसेक्स की अन्य कंपनियों में भारती एयरटेल , मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस , हिंदुस्तान यूनिलीवर , एनटीपीसी , टेक महिंद्रा, ट्रेंट , टीसीएस और टाइटन के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए जबकि दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक , एचडीएफसी बैंक, बीईएल , एलएंडटी, पावरग्रिड, बजाज फिनसर्व प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स , महिंद्रा एंड महिंद्रा , आईटीसी , टीएमपीवी, एचसीएल टेक , टाटा स्टील , कोटक महिंद्रा बैंक , के शेयर गिरे।

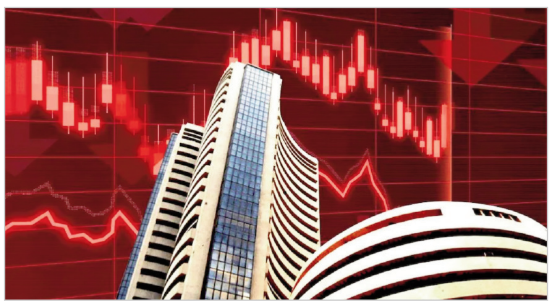

इससे पहले आज सुबह बाजार` गिरावट के साथ खुले। शुरुआत में सेंसेक्स 300 से अधिक अंक टूटकर 85,325 पर खुला। हालांकि इसके बाद कुछ रिकवरी देखने को मिली। इसी तरह निफ्टी भी कमजोरी के साथ 26,087 पर खुलने के कुछ देर बाद यह 57.85 अंक की गिरावट के साथ 26,117 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजारों की बात करें तो मंगलवार को एशियाई इंडेक्स में मजबूती दिखी। कोस्पी 1.02 फीसदी मजबूती के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में 0.54 फीसदी चढ़ा, हालांकि जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड में उछाल आया और 10-वर्षीय यील्ड 1.88 फीसदी तक पहुंच गई, जो 2008 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। उधर, वॉल स्ट्रीट पर क्रिप्टो-प्रेरित बिकवाली से निवेशकों की धारणा कमजोर रही। एसएंडपी 500 में 0.53 फीसदी, नैस्डैक में 0.38 फीसदी और डॉव जोन्स में 0.9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

विप्रो ने हरमन की डीटीएस इकाई का 37.5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया

- विप्रो की बड़े पैमाने पर नवाचार करने की क्षमता बढ़ेगी

नई दिल्ली।

बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी सेवा कंपनी विप्रो ने हरमन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस (डीटीएस) कारोबार इकाई का अधिग्रहण नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद पूरा कर लिया है। यह अधिग्रहण 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 3,270 करोड़ रुपये) में हुआ। कंपनी ने 21 अगस्त 2025 को इस सौदे की घोषणा की थी। विप्रो ने कहा कि डीटीएस का अधिग्रहण कृत्रिम मेधा (एआई) क्षमताओं, इंजीनियरिंग नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)उत्कृष्टता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विप्रो की एंड-टू-एंड इंजीनियरिंग सेवाओं की पेशकश मजबूत होगी और बड़े पैमाने पर नवाचार करने की क्षमता बढ़ेगी। विप्रो के प्रबंध साझेदार और इंजीनियरिंग के वैश्विक प्रमुख ने कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी को जटिल व्यावसायिक बदलावों को समर्थन देने और मापनीय व्यावसायिक मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। डीटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि विप्रो की वैश्विक पहुंच और उन्नत तकनीकी क्षमताएं नए उद्योगों में विस्तार और ग्राहकों को बेहतर समाधान देने का आधार प्रदान करेंगी। इस अधिग्रहण के साथ, विप्रो ने अपनी

तकनीकी और नवाचार क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है, जिससे यह उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करेगा।

वेकफिट का आईपीओ आठ दिसंबर को खुलेगा

- मूल्य दायरा 185-195 रुपये प्रति शेयर

नई दिल्ली । घरेलू सामान एवं फर्नीचर बनाने वाली कंपनी वेकफिट इनोवेशंस ने अपने 1,289 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 185-195 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। बेंगलुरु स्थित कंपनी का आईपीओ आठ दिसंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक पांच दिसंबर को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ 377.18 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और करीब 912 करोड़ रुपये मूल्य के 4,67,54,405 शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। इससे कुल मिलाकर इसका आकार 1,289 करोड़ रुपये बैठता है। कंपनी के शेयर 15 दिसंबर को बाजार में सूचीबद्ध होंगे।

यात्री वाहन बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मारुति सुजूकी अग्रणी

- जीएसटी कटौती और मांग ने दिया बड़ा सहारा

नई दिल्ली ।

नवंबर 2025 में भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री लगभग 4,25,000 इकाई रही, जो पिछले साल की इसी अवधि में 3,52,000 वाहनों से 20.7 फीसदी अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई जीएसटी कटौती और त्योहारी सीजन की मांग ने इस वृद्धि को मजबूती दी है। भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के अनुसार, अक्टूबर में भी घरेलू थोक बिक्री 17.2 फीसदी बढ़कर 460,739 वाहन रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत मांग और जीएसटी कटौती के कारण भारत का वाहन बाजार तेजी से बढ़ रहा है। मारुति सुजूकी की घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री, जो डीलरों को भेजी गई एक साल पहले के मुकाबले 21 फीसदी 1,70,971 इकाई हो गई। मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआईएल) के एक वरिष्ठ कार्य अधिकारी ने कहा कि दिसंबर में थोक बिक्री भी अच्छी रहने की उम्मीद है क्योंकि उत्पादन टीम उच्च मांग को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस साल नवंबर में वाहन उद्योग की यात्री वाहनों की थोक बिक्री लगभग 4,25,000 गाड़ियों की रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में करीब 3,52,000 गाड़ियां बिकी थीं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में वाहन उद्योग की कुल यात्री वाहनों की बिक्री 5 से 6 फीसदी के दायरे में रहने की उम्मीद है। भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम ने 14 नवंबर को कहा था कि त्योहारी सीजन और जीएसटी में कमी के बीच उच्च मांग के कारण इस साल अक्टूबर में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 17.2 फीसदी बढ़ी हैं और 460,739 गाड़ियां बिकी हैं। नवंबर में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू यात्री वाहनों थोक बिक्री 56,336 इकाई रही, जिसमें कि एक साल पहले के मुकाबले 21.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। ह्युंडै मोटर इंडिया की घरेलू पीवी थोक बिक्री नवंबर में एक साल पहले के मुकाबले 4.3 फीसदी बढ़कर 50,340 इकाई हो गई।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में किया बदलाव

- ओवरलिमिट के नाम पर नहीं चलेगा बैंक का खेल

नई दिल्ली । डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच देश में क्रेडिट कार्ड का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लेकिन कई बार ग्राहक अनजाने में अपनी निर्धारित कार्ड लिमिट से अधिक खर्च कर लेते हैं, जिसके कारण बैंकों द्वारा भारी ओवरलिमिट शुल्क लगाया जाता है। ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम करोड़ों कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब कोई भी बैंक या कार्ड जारीकर्ता ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ओवरलिमिट फीचर सक्रिय नहीं कर सकेगा। पहले कई बैंक इस सुविधा को स्वतः सक्रिय कर देते थे, जिससे ग्राहक अनजाने में अपनी लिमिट से अधिक खर्च कर बैठते थे और बाद में उन्हें भारी ओवरलिमिट चार्ज चुकाना पड़ता था। आरबीआई ने इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड जारीकर्ताओं को अपने मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल फीचर उपलब्ध कराना होगा। इस फीचर के माध्यम से ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार ओवरलिमिट सुविधा को ऑन या ऑफ कर सकेंगे। यह विकल्प 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ग्राहक ने ओवरलिमिट की अनुमति नहीं दी है, तो कार्ड किसी भी स्थिति में निर्धारित लिमिट से अधिक खर्च की अनुमति नहीं देगा।

रिलायंस रिटेल ने अपने उपभोक्ता कारोबार का पुनर्गठन पूरा किया

- एफएमसीजी कारोबार अब नई इकाई न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में

नई दिल्ली ।

रिलायंस रिटेल ने अपने उपभोक्ता कारोबार का पुनर्गठन पूरा कर लिया है। इसके तहत एफएमसीजी (दैनिक उपभोग की वस्तुएं) ब्रांड व्यवसाय को नई इकाई न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (न्यू आरसीपीएल) में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कदम 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। अब न्यू आरसीपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की प्रत्यक्ष सहायक कंपनी बन गई है। न्यू आरसीपलएल में आरआईएल का हिस्सा 83.56 प्रतिशत होगा, जबकि आरआरवीएल में अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी 16.44 प्रतिशत रहेगी। आरआरवीएल के शेयरधारकों को न्यू आरसीपलएल में शेयर आवंटित किए जाएंगे, दर के अनुसार आरआरवलीएल के दो शेयर न्यू आरसीपलएल का एक शेयर। इस प्रक्रिया के तहत आरआरवीएल की पूर्व-योजना की चुकता शेयर पूंजी रद्द और कम कर दी जाएगी। आरआईएल ने 17 अक्टूबर को अपने नवीनतम आय विवरण में कहा था कि आरसीपीएल ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 9,850 करोड़ रुपये का सकल राजस्व दर्ज किया। रिलायंस ने 2022 में एफएमसीजी बाजार में प्रवेश किया।

उसके बाद से इसने कैंपा कोला सहित कई ब्रांड का अधिग्रहण किया और कई नए ब्रांड पेश किए हैं। इसकी उपस्थिति कोला से लेकर साबुन, स्टेपल, डिशवॉशिंग लिक्विड, डिटर्जेंट और फ्लोर क्लीनर तक के एफएमसीजी खंड में है। आरआरवीएल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 3.30 लाख करोड़ रुपये का एकीकृत कारोबार किया था।

पोस्ट ऑफिस की टीडी योजना: निवेश एक लाख, पांच वर्ष में ब्याज रिटर्न 44,995 रुपए

- पांच वर्षीय टीडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर लागू

नई दिल्ली ।

पोस्ट ऑफिस की पांच वर्षीय टाइम डिपॉजिट (टीडी) योजना उन निवेशकों के लिए आदर्श है, जो शून्य जोखिम वाले निवेश की तलाश में हैं। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है और निवेशकों को निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न देती है। इस योजना में निवेशक 1, 2, 3 या 5 वर्ष के लिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें पांच वर्षीय टीडी सबसे लोकप्रिय है। पांच वर्षीय टीडी निवेशकों को स्थिर और गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स लाभ भी देता है।

निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि में सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। निवेश करने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में टीडी खाता खोलना होगा। आवश्यक केवायसी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड और फोटो जमा करना अनिवार्य है। खाता नकद, चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिए तुरंत खोला जा सकता है। खाता सिंगल या जॉइंट भी हो सकता है।

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की पांच वर्षीय टीडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर लागू है। 1,00,000 रुपये निवेश करने पर 5 वर्षों में कुल रिटर्न 44,995 रुपये होगा और मेच्योरिटी राशि 1,44,995 रुपये तक पहुंच जाएगी। ब्याज सालाना भुगतान होता है, लेकिन गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रायपुर वनडे से पहले स्टेन का बड़ा बयान: रोहित-विराट का जलवा कायम, डी कॉक पर सबकी निगाहें

रांची (एजेंसी)। रायपुर में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए, रांची में पहले वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद वरिष्ठ बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को कुछ साबित करना होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे बुधवार को रायपुर में होगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है।

रांची में पहले वनडे में विराट कोहली (135), केएल राहुल (60) और रोहित शर्मा (58) ने यादगार बल्लेबाजी की, जिससे भारत 349/8 पर पहुंच गया। 11/3 से पिछड़ने के बाद, मैथ्यू ब्रीट्ज़के (72), मार्को जेनसन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) की प्रोटियाज तिकड़ी ने प्रोटियाज को जीत के करीब पहुंचाया। दूसरे वनडे से अपनी उम्मीदों पर बात करते हुए, जियोस्टार विशेषज्ञ स्टेन ने कहा कि मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि कौन से तेज़ गेंदबाज़ और कौन से स्पिनर कुछ दिलचस्प करते हैं। यह अब तक बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग रहा है, तो कौन से गेंदबाज़ दूसरे वनडे में अच्छा प्रदर्शन करेंगे? क्विंटन डी कॉक ने पहले वनडे में कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बात साबित करनी होगी। वह ऐसे गेंदबाज़ हैं जिन पर दक्षिण अफ्रीका बड़ा स्कोर बनाने के लिए निर्भर करेगा।

इस साल वनडे से संन्यास लेने के बाद सफ़ेद गेंद से वापसी करने के बाद से, डी कॉक ने वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने चार मैचों में 79.66 की औसत और 91 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 123* रन रहा है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाफ है, उन्होंने भारत के खिलाफ 51.28 की औसत से 1,077 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं तथा उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है।

महिला क्रिकेटरों स्नेह राणा, प्रतीका रावल ओर रेणुका सिंह का हुआ प्रमोशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 2025 विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तीन खिलाड़ियों स्नेह राणा, प्रतीका रावल और रेणुका सिंह ठाकुर को प्रमोशन दिया है। रेलवे ने इन तीनों को ही आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देते हुए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी- स्पोर्ट्स) के पद पर नियुक्त किया है। इन तीनों खिलाड़ियों को अब ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) की इस पहल से महिला क्रिकेटरों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी मिलेगी।

गौरतलब है कि महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन इस बार भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था। इसके खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता था।

राणा सहित तीनो ही क्रिकेटरों ने इस सम्मान और प्रमोशन के लिए रेलवे का आभार जताते हुए कहा है कि इससे उनको और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। राणा को

राणा हाल ही में महिला प्रीमियर लीग नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। गत सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलने के बाद राणा अब जेमिमा रोड्रिग्स और शैफाली वर्मा के साथ कैपिटल्स की ओर से खेलती नजर आयेंगी।

वैभव सूर्यवंशी की नाबाद शतकीय पारी बेकार गई, महाराष्ट्र के खिलाफ हारा बिहार

कोलकाता (एजेंसी)। प्रतिभावान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 61 गेंद में नाबाद 108 रन की पारी के बावजूद बिहार को मंगलवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप बी मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर बिहार ने 14 साल के सूर्यवंशी की नाबाद पारी से तीन विकेट पर 176 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और सात छक्के मारे और टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इसके जवाब में महाराष्ट्र ने कप्तान पृथ्वी साव की 30 गेंद में 66 रन की पारी के अलावा नीरज जोशी(30), रंजीत निकम (27) और निखिल नाईक (22) की पारियों से पांच गेंद शेष रहते सात विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की। मोहम्मद इजहार (22 रन पर दो विकेट) और सकीबुल गनी (50 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाकर बिहार को मैच में बनाए रखा लेकिन महाराष्ट्र ने अंततः धैर्य बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले सूर्यवंशी ने सात छक्के जड़ बिहार की ओर से टी20 पारी में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने आयुष लोहारुका (नाबाद 25) के साथ चौथे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। सूर्यवंशी ने अंतिम ओवर में अर्शिन कुलकर्णी पर चौके के साथ शतक पूरा किया। जाधवपुर यूनिसर्विटी मैदान पर गोवा ने मध्य प्रदेश को सात विकेट से हराया। मध्य प्रदेश के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा ने सुयश प्रभुदेसाई (नाबाद 75) और अभिनव तेजराणा (55) के अर्धशतक से 18.3 ओवर में तीन विकेट पर171 रन बनाकर जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश ने इससे पहले हरप्रीत सिंह के 80 रन की बदौलत छह विकेट पर 170 रन बनाए।

आईपीएल2026 नीलामी: 2 करोड़ बेस प्राइस पर ग्रीन, लिविंगस्टोन; वेंकटेश-बिश्नोई लिस्ट में, मैक्सवेल क्यों नहीं?

मुम्बई (एजेंसी)। कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर और मथीशा पथिराना उन 45 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी में 2 करोड़ रुपये के उच्चतम आधार मूल्य के साथ प्रवेश किया है। कुल 1,355 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है और 30 नवंबर को पंजीकरण बंद होने के बाद सोमवार को फ्रेंचाइजी के साथ साझा किया। प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम बनाने की अनुमति है और इस साल 77 स्थान उपलब्ध हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।

आईपीएल सभी दस टीमों से इच्छा सूची प्राप्त करने के बाद इस सूची को छोटा करेगा। 16 दिसंबर को अबू धाबी में दिन भर चलने वाली नीलामी से पहले, फ्रेंचाइजी को अपनी शॉर्टलिस्ट जमा करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों में, प्रमुख भूमिकाओं में विशेषज्ञ खिलाड़ी बड़ी बोलियां आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन सुर्खियाँ ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर टिकी हैं, जिन्होंने पीठ की चोट के कारण 2025 की मेगा-नीलामी को छोड़ दिया था। जिन टीमों के मजबूत रुचि दिखाने की उम्मीद है, उनमें कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) (64.3 करोड़ रुपये का पर्स) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) (43.4 करोड़ रुपये) शामिल हैं, दोनों के पास स्वस्थ बजट हैं।

केकेआर, विशेष रूप से वेस्टइंडीज के टी20 दिग्गज आंद्रे रसेल के हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने के बाद, ग्रीन पर आक्रामक रूप से काम कर सकता है। ग्रीन की बहुमुखी प्रतिभा, वह क्रम में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, सीम-अप गेंदबाजी कर सकते हैं, और क्षेत्ररक्षण में भारी योगदान दे सकते हैं, उन्हें इस साल सबसे अधिक मांग वाले नामों में से एक बनाता है। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर सहित नौ खिलाड़ियों को रिलीज़ किया, जिनकी कीमत उन्हें पिछले साल की मेगा-नीलामी में 23.5 करोड़ रुपये लगी थी। अब उनके पास भरने के लिए 12 स्थान हैं, जिनमें छह विदेशी शामिल हैं। पांच बार की चैंपियन सीएसके में नौ रिक्तियां हैं, जिनमें से चार विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।

इस नीलामी से पहले रिलीज़ किए गए कई खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रुपये की शीर्ष मूल्य सीमा को चुना है। इसमें श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना भी शामिल हैं, जिन्हें सीएसके ने पिछले साल 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन डेथ ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में उनकी कीमत के बावजूद, चोट से जूझने के बाद रिलीज़ कर दिया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, भी एक निराशाजनक सीज़न के बाद खुद को पूल में वापस पाते हैं।

भारतीय खिलाड़ियों में, वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई, दोनों ने खुद को 2 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर सूचीबद्ध किया है। बिश्नोई, जिन्हें पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, को फ्रैंचाइज़ी के साथ चार सीज़न बिताने के बाद जाने दिया गया। इस लंबी सूची में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम शामिल नहीं है। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने पिछले सीज़न में उन्हें 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब 37 वर्षीय मैक्सवेल की 2025 सीज़न के बीच में उंगली में फ्रैक्चर हो गया और उनकी जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल ओवेन को शामिल किया गया है, जिन्हें रिटेन किया गया है।

शास्त्री बोले, गंभीर की जगह मैं होता तो हार की पूरी जिम्मेदारी लेता

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने टेस्ट क्रिकेट में टीम के खराब प्रदर्शन पर निराशा जतायी है। शास्त्री के अनुसार टीम के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने से कोच कोच गौतम गंभीर बच नहीं सकते। कोच के अलावा टीम के खराब प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी भी जिम्मेदार हैं क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विकेट गिरे उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक विकेट को स्पिनरों से अधिक

सहायता मिलने की बात है। उसका भी बहाना नहीं चलेगा क्योंकि हम शुरुआत से ही ऐसे ट्रैक पर खेलते रहे हैं। 2012 से 2024 तक घरेलू धरती पर एक भी सीरीज नहीं हारने वाली भारतीय टीम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद 2 घरेलू सीरीज हारी है। उसे पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया। वहीं अब दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से पराजित किया है। शास्त्री ने कहा कि अगर ये उनके साथ होता तो वह सारी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में जिस प्रकार 100 रन पर एक विकेट से 130 रन पर 7 विकेट गिरे हैं। ये टीम खराब भी नहीं है। उनके पास बहुत प्रतिभा है। खिलाड़ियों को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप क्रिकेट खेलने की जब शुरुआत करते हैं, तब से स्पिन खेले हैं।' जब ने उनसे ये पूछा कि क्या वह मुख्य कोच गंभीर का बचाव कर रहे हैं, तब शास्त्री ने कहा, मैं (उनका) बचाव नहीं कर रहा। सौ फीसदी वह भी जिम्मेदार हैं। शास्त्री जब कोच थे तब विराट कोहली टीम के कप्तान थे। उस समय भारतीय टीम घर में हराने और सीरीज जीतने की ताकत रखती थी। शास्त्री-कोहली के समय में भारतीय टीम अपनी धरती पर केवल दो टेस्ट हारी थी। शास्त्री भारत के सबसे सफल कोच में से एक हैं। उनके कार्यकाल में 2017 से 2021 तक भारत का टेस्ट में जीत का रिकार्ड 65 का रहा था।

लंबी अवधि के प्रारूप मुझे रास आते हैं, विकेटों के बीच दौड़ने पर कोहली से सलाह लेता हूं : तिलक वर्मा

मुम्बई। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को लंबे प्रारूपों में खेलना रास आता है और वह विराट कोहली से फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में सलाह ले रहे हैं ताकि आने वाले मौकों का पूरा फायदा उठा सकें। तेइस वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक सिर्फ चार वनडे खेले हैं जबकि उन्हें टेस्ट टीम में मौका मिलने का इंतजार है। उन्होंने

कहा कि मौजूदा वनडे श्रृंखला में टीम में कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। तिलक ने 'जियोस्टार' से कहा, '' वनडे और टेस्ट क्रिकेट मेरे खेल के मुताबिक है और मैं इसका अधिक लुत्फ उठाता हूं। मैं और वनडे खेलने के लिए उत्साहित हूं। जब रोहित भाई और विराट भाई एक ही टीम में होते हैं, तो आत्मविश्वास का स्तर बिल्कुल अलग होता है।'' उन्होंने रोहित और कोहली की तारीफ करते हुए कहा, ''उनके पास अपार अनुभव और ज्ञान है। मैं बेहतर होने के लिए उनसे ज्यादा से ज्यादा सलाह लेने की कोशिश करता हू।' इस युवा वामहस्त बल्लेबाज ने कहा कि वह कोहली से खास तौर पर फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में सलाह लेते रहे हैं क्योंकि वह इस मामले में वह उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं। तिलक ने कहा, ''मैं विराट भाई से काफी बात करता हूं, खासकर फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ के बारे में उनकी सलाह लेता हूं। मुझे भी दौड़ना पसंद है और मुझे लगता है कि इस मामले में मैं काफी तेज हूं। '' दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला के बारे में तिलक ने कहा, ''दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुझे जब भी मौके मिलेंगे, मैं उन मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहूंगा। मैं वनडे और टेस्ट में भी खुद को साबित करना चाहता हूं।

जूनियर महिला वर्ल्ड कप : भारत की नामीबिया पर बड़ी जीत, 13-0 से हराया

सैंटियागो (चिली) (एजेंसी)। भारतीय टीम ने पूल सी के अपने पहले मैच में नामीबिया को 13-0 से रौंद कर महिला एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। सेंट्रो डेपोर्टिवो डे हॉकी सेस्पेड एस्टाडियो नैशनल में खेले गये मुकाबले में भारतीय टीम के लिए कनिका सिवाच ने (12वें, 30वें, 45वें) मिनट और हिना बानो (35वें, 35वें, 45वें) मिनट में शानदार हैट्रिक लगाकर स्कोरिंग में सबसे आगे रहीं, जबकि साक्षी राणा ने (10वें, 23वें) मिनट में दो गोल किए।

भारत के शानदार प्रदर्शन में बिनिमा धन ने (14वें), सोनम ने (14वें), साक्षी शुक्ला ने (27वें), इशिका ने (36वें), और मनीषा ने (60वें) मिनट में एक-एक गोल किया। भारत ने शुरू में ही लय बना ली और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। 10वें मिनट में सफलता मिली जब साक्षी राणा ने एक तेज रिवर्स फ्लिक से गोल किया। कनिका सिवाच ने जल्द ही एक जबरदस्त फिनिश के साथ अपना दूसरा गोल किया। इससे पहले बिनिमा धन और सोनम के तेज स्ट्राइक ने पहले क्वार्टर के आखिर तक स्कोर 4-0 कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में भी एकतरफा मुकाबला जारी रहा जब राणा ने अपना दूसरा गोल किया, और साक्षी शुक्ला ने पेनल्टी-कॉर्नर ड्रैगफ्लिक को गोल में बदला। सिवाच ने हाफ-टाइम से ठीक पहले एक और गोल करके बढ़त को 7-0 कर दिया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी उसी लय के साथ शुरुआत की। हिना बानो ने जल्दी-जल्दी दो गोल किए, जिसमें एक टॉप-कॉर्नर फिनिश भी शामिल था, इसके बाद इशिका ने एक रिबाउंड पर गोल करके स्कोर डबल-डिजिट तक पहुंचाया।

बानो ने पेनल्टी-कॉर्नर डिफ्लेक्शन से अपनी हैट्रिक पूरी की और सिवाच ने कुछ ही पल बाद अपनी हैट्रिक पूरी करके स्कोर को आखिरी क्वार्टर में 12-0 कर दिया। कई रोटेशन के बावजूद, भारत का दबदबा बना रहा और मनीषा के आखिरी पेनल्टी-कॉर्नर पर किए गए गोल ने 13-0 की जीत पूरी की। भारतीय टीम बुधवार को अपने अगले ग्रुप-स्टेज मैच में जर्मनी भिड़ेगी।

राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से खिलाड़ियों को लाभ होगा : लवलीना बोरगोहेन

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कहा है कि भारत के 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से उभरते हुए खिलाड़ियों को लाभ होगा। बोरगोहेन ने मेजबानी मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे युवा प्रतिभाओं को खेलों में आगे बढ़ने और वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। भारतीय मुक्केबाज़ ने कहा कि यह देश के लिए एक अच्छा है क्योंकि जब देश में कोई बड़ी प्रतियोगिता होती है, तो खिलाड़ियों को और भी अवसरा मिलते हैं। यह गुजरात में आयोजित होगा, इसलिए वहां के खिलाड़ियों को विशेष लाभ होगा। इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के अधिकार मिलने पर प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की सामूहिक प्रतिबद्धता ने वैश्विक खेल मंच पर भारत का स्थान मज़बूती से स्थापित किया है। बररहाल खिलाड़ी इन खेलों की तैयारियों को शुरु करने लगे हैं। निशानेबाज सरबजोत सिंह ने कहा कि 2030 में होने वाले इन खेलों को लेकर वह उत्साहित है। उन्होंने कहा कि यह ये खेल अहमदाबाद में आयोजित होगी, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इन खेलों में देश को कई पदक मिलना तय है। उन्होंने बताया कि वह हर दिन चार से पांच घंटे अभ्यास कर रहे हैं। वहीं हाल में कजाकिस्तान में एशियन शूंटिंग चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक विजेता आदित्य मालरा ने कहा है कि देश में राष्ट्रमण्डल खेलों को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि पहले भारत के खिलाड़ी बाहर इन खेलों को खेलने जाया करते थे, लेकिन अब बाहर विदेशों के खिलाड़ियों को भी भारत में यह खेल खेलने का अवसर मिल रहा है। मिलेगा।

38 की उम्र में रोहित की आक्रामक पारी देखकर हैरान हैं इरफान पठान

मुम्बई। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबले में आकामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की जमकर प्रशंसा की है। रोहित ने पहले ही एकदिवसीय में शानदार पारी के साथ ही दिखाया है कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बचा है। टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद रोहित की यह पारी दिखाती है कि उनका फार्म अब भी बरकरार है। इसी को लेकर पठान ने कहा कि 38 साल की उम्र में जिस प्रकार से रोहित ने बल्लेबाजी की है। उससे उनकी फार्म का अंदाजा होता है। पठान ने कहा, रोहित अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में दिख रहे हैं। वह 38 साल के हो गये ये लगता ही नहीं है। उन्होंने फिटनेस में काफी सुधार किया है पर जिस तरह उन्होंने हालातों को देखकर बल्लेबाजी की है। उससे अंदाजा होता है कि वह किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रोहित ने इस मैच में एक और बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने तीन छक्के लगाकर एकदिवसीय में तेजी से अपनी 350 छक्के पूरे किये हैं।

SMAT: हार्दिक पांड्या की पेशेवर क्रिकेट में धमाकेदार वापसी, ठोका शानदार अर्धशतक, बड़ौदा जीती

नई दिल्ली (एजेंसी)। लंबे समय बाद पेशेवर क्रिकेट में लौटे हार्दिक पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में आते ही ऐसा प्रभाव छोड़ा कि पूरे भारतीय क्रिकेट जगत की नजरें उनकी ओर टिक गईं। हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले में हार्दिक ने सिर्फ 42 गेंदों पर नाबाद 77 रन ठोककर बड़ौदा को पंजाब पर यादगार जीत दिला दी। यह पारी न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की पुरानी चमक को दर्शाती है, बल्कि उनके ऑलराउंड कौशल का भी शानदार उदाहरण है। उनकी यह वापसी आने वाले दिनों में भारतीय टीम संयोजन के लिए भी बड़े संकेत देती है।

हार्दिक की आतिशी पारी ने पलटा मैच का मोमेंटम

बड़ौदा के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी वापसी मैच को एक विशेष मौके में बदल दिया। 42 गेंदों में नाबाद 77 रन की तूफानी पारी में सात चौके और चार छक्के शामिल थे। उनकी बैटिंग में वही पुरानी ताकत, टाइमिंग और मैच को हाथ में लेने की क्षमता साफ दिखाई दी। पारी की शुरुआत ठंडी थी, लेकिन हार्दिक ने आते ही रफ्तार पकड़ी और पंजाब बॉलिंग अटैक की लाइन-लेथ को पूरी तरह हिला दिया। एक समय मुश्किल लग रहा लक्ष्य हार्दिक की आक्रामक बल्लेबाजी से बेहद आसान हो गया।

शिवालिक शर्मा के साथ 101 रन की गेम-चेंजिंग पार्टनरशिप

हार्दिक के दमदार प्रदर्शन का सबसे अहम हिस्सा रहा शिवालिक शर्मा के साथ उनकी 101 रन की साझेदारी। शिवालिक ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए और बेहद समझदारी से रिटायर्ड आउट होकर हार्दिक को एंड पर स्ट्राइक रखने का मौका दिया।

इस साझेदारी ने मैच का पूरा रूख बदल दिया और बड़ौदा को अंत में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम को आखिरी 15 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, लेकिन नए बल्लेबाज जितेश शर्मा के आने के बाद चीजें और आसान हो गईं।

बड़ौदा का दबदबा

जितेश शर्मा ने आते ही तेजी से रन जोड़े और हार्दिक का शानदार साथ निभाया। केवल 9 गेंदों में बड़ौदा ने जरूरी रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। लक्ष्य भले ही बड़ा लग रहा था, लेकिन हार्दिक की शानदार टाइमिंग और आक्रामक अंदाज ने पंजाब की गेंदबाजी को बेअसर कर दिया।

हार्दिक का गेंदबाजी प्रदर्शन : महंगा लेकिन प्रभावी

बल्लेबाजी के अलावा हार्दिक ने गेंद से भी योगदान दिया। हालांकि उनका चार ओवर का स्पेल थोड़ा महंगा रहा (52 रन), लेकिन उन्होंने 1 विकेट चटकाया। उनकी गेंदबाजी की लय अभी पूर्ण रूप से लौटती नहीं दिखी, लेकिन वापसी मैच को देखते हुए यह प्रयास सराहनीय माना जा रहा है। आने वाले मुकाबलों में वे और बेहतर लय में लौट सकते हैं।

पंजाब की तेज शुरुआत भी नहीं दिला सकी जीत

पंजाब की ओर से अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 19 गेंदों में फिफ्टी लगाकर शानदार शुरुआत दी। उनके अलावा अनमोलप्रीत सिंह ने 32 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली। इन दोनों की तेज बल्लेबाजी से पंजाब का स्कोर मजबूत दिख रहा था, लेकिन उनकी गेंदबाजी हार्दिक और शिवालिक की साझेदारी को रोक नहीं पाई।

ग्रुप सी की स्थिति, गुजरात शीर्ष पर

इस जीत के बाद ग्रुप सी में बड़ौदा और पंजाब दोनों के दो-दो मैच पूरे हो चुके हैं। वहीं गुजरात चार मैचों में तीन जीत के साथ ग्रुप में सबसे आगे है। हार्दिक की यह वापसी न सिर्फ बड़ौदा के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, जो उन्हें फिर से अपने पुराने अंदाज में देखने के लिए उत्सुक थे।

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट के लिए घोषित की टीम, वुड की जगह जैक्स को शामिल किया

ब्रिसबेन। इंग्लैंड ने गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां शुरु हो रहे दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में बदलाव करते हुए तीन साल से टीम से बाहर चल रहे स्पिन ऑलराउंडर विल जैक्स को चोटिल मार्क वुड की जगह शामिल किया है। दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से गाबा मैदान में खेला जाएगा। यह इंग्लैंड की टीम में एकमात्र बदलाव है। पर्थ में पहले टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड ने एक स्पिनर को भी रखने का फैसला किया है। जैक्स को शुएब बशीर पर इसलिए वरीयता दी गयी है क्योंकि वह बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। जैक्स ने इससे पहले इंग्लैंड के लिए दो टेस्ट मैच खेले हैं और 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में पांच विकेट लिए थे।

इंग्लैंड टीम इस प्रकार है : बेन स्टोक्स (कप्तान), जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार पर ब्रिटिश सांसद ने जताई चिंता

लंदन, एजेंसी। ब्रिटिश संसद में लेबर पार्टी के सांसद जॉन मैकडॉनेल ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तानी बलों के जरिये सरकार समर्थित अपहरणों और ड्रोन हमलों पर ध्यान आकर्षित किया। मैकडॉनेल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में तीन लिखित संसदीय प्रश्न और एक अर्ली डे मोशन दायर किया है।

फ्रांस : घर में लगी आग में दंपती समेत पांच लोगों की मौत

पेरिस, एजेंसी। पूर्वी फ्रांस के एक कस्बे में आग लगने से एक घर में मौजूद पांच लोगों की मौत हो गई। म्यूर्थ-ए-मोसेले विभाग ने रविवार को बताया कि न्यूवेस-मैसंस शहर में लगी आग पर काबू पाने के लिए रातभर 70 दमकलकर्मी व लगभग 40 वाहनों को तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी महसूस करने वाले छठे व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। वह खतरे से बाहर है। पीड़ितों में दंपती और 17 से 20 वर्ष की आयु के तीन युवा शामिल थे।

चीन में रिकॉर्ड 37 लाख लोगों ने दी सिविल सेवा की परीक्षा

बीजिंग, एजेंसी। चीन में रविवार को 37 लाख से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा दी। चीन में सिविल सेवा के लिए उम्र सीमा को 35 साल से अधिक बढ़ाने के बाद यह पहली राष्ट्रीय परीक्षा थी। यह रिकॉर्ड संख्या देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों की मांग को दर्शाती है। राज्य संचालित समाचार एजेंसी ने बताया कि इस परीक्षा में औसतन प्रति सीट 98 आवेदक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन रिक्तियों में से लगभग 70 प्रतिशत कॉलेज के नए स्नातकों के लिए आरक्षित हैं।

सीरिया में लोकतंत्र अभी दूर, पर सुधार अच्छा : एमनेस्टी इंटरनेशनल

दमिश्क, एजेंसी। गैर सरकारी वैश्विक मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने शनिवार को कहा कि सीरिया में नई सरकार ने सुधारों और संक्रमणकालीन न्याय के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन लोकतंत्र की कमी अभी भी है। बशर असद की सरकार गिरने के एक साल बाद कैलामार्ड का कहना है कि कानूनी सुधार योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों का स्वागत होना सकारात्मक संकेत है।

ताइवान : चीनी सेना के 25 विमानों ने क्रॉस की मध्य रेखा

ताइपे , एजेंसी। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने रविवार को बताया कि उनके क्षेत्र के आसपास चीन के पीएलए के 27 विमानों, 11 नौसैनिक जहाजों और तीन सरकारी जहाजों को देखा गया। एमएनडी के अनुसार, 27 विमानों में से 25 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश किया। इन विमानों में शेनयांग जे-16 और भारी बॉम्बर शियान एच-6 शामिल थे। एमएनडी ने कहा कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। ताइवान ने कहा कि चीन जापान के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के बेस में घुस गए हमलावर, खुद को बम से उड़ाया ; तीन मारे गए

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 24 घंटे के अंदर ही कम से कम सात धणाके हुए। वहीं बलूचिस्तान के नोकुंडी में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के गेट पर फिदायीन हमला किया गया। हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। प्रशासन का कहना है कि यह हमला तहरीक-ए-तालिबान ने किया है। पाकिस्तान के अर्द्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन में तीन हमलावरों को मार गिराने का दावा किया गया है। बलूचिस्तान साउथ के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुताबिक हेडक्वार्टर के गेट पर ही जबरदस्त आवाज हुई। इसके बाद तुरंत सुरक्षाबलों ने अभइयान शुरू कर दिया। बताया गया कि कम से कम 6 हमलावर हेडक्वार्टर में दाखिल हुए थे। एफी के प्रवक्ता ने बताया कि जब तक सभी आतंकियों को मारा नहीं जाता, ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षाबल हर कमरे की ठीक से जांच कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले पेशावर में फ्रंटियर कॉर्प्स के परिसर में फिदायीन हमला हुआ था जिसमें तीन की जान चली गई थी। वहीं क्वेटा में पैरामिलिट्री बेस में कार में हुए धमाके से भी इलाका दहल गया था। पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों से इस तरह के हमले तेजी से बढ़े हैं। साभर में ही बलूचिस्तान में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कई बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी हमलों की जिम्मेदारी ली है।

भारतीयों ने ही अमेरिका को सुपरपावर बनाया: एलन मस्क

वाशिंगटन, एजेंसी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने रविवार को कई दिनों की अटकलों के बाद आखिरकार जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के पॉडकास्ट पिपुल बाय डब्ल्यूटीएफ में साफ कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका को कुशल भारतीय प्रतिभाओं के आने से भारी लाभ हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने आखिरकार वो बात बोल ही दी, जिसे सुनकर अमेरिका के अंदरूनी इमिग्रेशन-विरोधी गुटों के होश उड़ गए। जीरोधा के निखिल कामथ के पॉडकास्ट में मस्क ने साफ-साफ कहा कि अमेरिका को पिछले दशकों में जितना फायदा हुआ है, उसका बड़ा हिस्सा भारतीय टैलेंट की वजह से हुआ है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लोग इसका जीता-जागता सबूत हैं। और तो और, जब एच1-बी वीजा को लेकर ट्रंप कैंप में घमासान मचा हुआ है, तब मस्क ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस प्रोग्राम का दुरुपयोग हुआ है, इसे ठीक करो, लेकिन बंद करोगे तो अमेरिका खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत को मार डालेगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब हजारों भारतीयों का सदियों पुराना अमेरिकी सपना (ऊंची पढ़ाई, मोटी सैलरी वाली नौकरियां, बेहतर लाइफस्टाइल और तरक्की का वादा) सख्त होते वीजा नियमों और अचानक नीतिगत बदलावों की वजह से तेजी से फीका पड़ता दिख रहा है। मस्क ने कहा कि मेरा मानना है कि अमेरिका को यहां

आए टैलेंटेड भारतीयों से बहुत फायदा हुआ है। इस दौरान निखिल कामथ ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे सफल भारतीयों का उदाहरण दिया, जो दशकों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप के एच1-बी प्रोग्राम का समर्थन करने के कुछ ही दिन बाद रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इसे धीरे-धीरे खत्म करने का बिल पेश कर दिया और दावा किया कि यह अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीन रहा है। ऐसे कदम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा खतरा हैं, क्योंकि एच1-बी उनके लिए ग्रीन कार्ड और फिर अमेरिकी नागरिकता का सबसे आम रास्ता रहा है। ट्रंप 2.0 सरकार में सरकारी दक्षता विभाग के हेड रहे मस्क ने कहा कि बाइडेन प्रशासन में बॉर्डर कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं थी। बिना बॉर्डर कंट्रोल के आप देश नहीं कहला सकते। बाइडेन के समय बड़े पैमाने पर अवैध इमिग्रेशन हुआ, जिससे नेगेटिव सिलेक्शन इफेक्ट पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अगर अवैध तरीके से अमेरिका आकर ढेर सारे सरकारी लाभ मिल रहे हैं, तो आप गलत तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह एक गलत इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। बॉर्डर कंट्रोल न होना बिल्कुल बेतुका था। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले की इमिग्रेशन पॉलिसी पर बोलते हुए मस्क ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आम अमेरिकी नागरिकों का यह डर बहुत वास्तविक है कि विदेशी टैलेंट उनकी नौकरियां छीन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा अपना अनुभव यही है कि टॉप टैलेंट हमेशा कम पड़ता है। मुश्किल काम करवाने के लिए आपको असाधारण लोग चाहिए। कुछ कंपनियां इसे सिर्फ कॉस्ट का खेल बना देती हैं। अगर अमेरिकी नागरिक से आधे या उससे भी कम पैसों में कोई काम कर दे तो वे उसे हायर कर लेती हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स जैसे अपने खुद के टॉप अमेरिकी कंपनियों का उदाहरण देते हुए मस्क ने कहा कि उनकी कंपनियां हमेशा बेस्ट टैलेंट ढूंढती हैं और उन्हें एवरेज से कहीं ज्यादा सैलरी देती हैं। इसलिए एच1-बी के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है, लेकिन प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करना सही नहीं। उन्होंने अंत में कहा कि हां, एच1-बी प्रोग्राम का कुछ कंपनियों ने दुरुपयोग किया है। खासकर कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने सिस्टम के साथ खेला है, उसे रोकना होगा। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं कि एच1-बी प्रोग्राम ही बंद कर देना चाहिए।

मस्क ने बताया- उनकी पत्नी को गोद लिया गया था : पॉडकास्ट के दौरान एलन मस्क ने कहा कि 'मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरी पार्टनर शिवॉन आधी भारतीय हैं। मेरे और उसके एक बेटे का मध्य नाम शेखर है, जो चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है।' मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस कनाडा में पली-बढ़ी हैं और जब वे एक छोटी बच्ची थीं, तब उन्हें गोद लिया गया था। शिवॉन जिलिस ने साल 2017 में मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जॉइन की थी और वे फिलहाल कंपनी में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम कर रही हैं। शिवॉन ने येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की है।

नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से मांगा क्षमादान, अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे के बीच किया अनुरोध

येरुशलम, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे के बीच देश के राष्ट्रपति से आधिकारिक रूप से माफी मांगी है। यह कदम इस्राइल की राजनीति में बड़ा और असाधारण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति कार्यालय के कानूनी विभाग को अपना माफी का आवेदन भेज दिया है। वहीं राष्ट्रपति कार्यालय ने इस आवेदन को 'असाधारण और दूरगामी असर वाला कदम' बताया है।

नेतन्याहू पर क्या हैं आरोप : बेंजमिन नेतन्याहू इस्राइल के इतिहास में पहले ऐसे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। उनके खिलाफ तीन बड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं। इसमें धोखाधड़ी, भरोसे का उल्लंघन, रिश्वत लेना शामिल हैं। इन मामलों में आरोप है कि नेतन्याहू ने अमीर व्यापारियों और राजनीतिक समर्थकों से उपहार और फायदे लिए और बदले में उन्हें लाभ पहुंचाया। हालांकि, अब तक किसी भी मामले में उनकी दोष सिद्धि नहीं हुई है। वह लगातार सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं।

नेतन्याहू का देशवासियों के लिए संदेश : इस्राइल के नागरिकों। मेरे खिलाफ जांच शुरू हुए लगभग दस साल हो गए हैं। इन मामलों में ट्रायल लगभग छह साल से चल रहा है और उम्मीद है कि यह कई और वर्षों

तक चलेगा। जैसे-जैसे कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी दलीलों को पूरी तरह से गलत साबित करने वाले बयान और सबूत सामने आ रहे हैं, और जैसे-जैसे यह साफ हो रहा है कि मेरे खिलाफ सबूतों का ढांचा गंभीर अपराध करते हुए बनाया गया था, मेरा निजी हित रहा है और रहेगा कि इस प्रोसेस को आखिर तक जारी रखा जाए जब तक कि मैं सभी आरोपों से पूरी तरह बरी न हो जाऊं। लेकिन सुरक्षा और राजनीतिक हकीकत, देश के हित, कुछ और ही चाहते हैं। इस्राइल देश बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और उनके साथ-साथ खतरों को दूर करने के बहुत सारे मौके भी हैं। इन मौकों को पाने के लिए देश की एकता जरूरी है। ट्रायल का जारी रहना हमें अंदर से तोड़ रहा है। फूट डालने की यह कोशिश फूट को और बढ़ाती है। मुझे यकीन है, देश के कई और लोगों की तरह, कि ट्रायल का तुरंत खत्म होना आग को कम करने और उस बड़े मेल-मिलाप को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेगा जिसकी हमारे देश को बहुत जरूरत है। मैंने इस मामले पर लंबे समय से बहस की है, लेकिन हाल ही में जो हुआ है।

भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की उम्मीद, नहीं प्रभावित होंगे संबंध: विदेश सलाहकार हुसैन

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने रविवार को कहा कि वह भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की उम्मीद करता है। लेकिन इस मुद्दे को नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनने देगा। ढाका में अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत हसीना को प्रत्यर्पित किए बिना बेहतर संबंधों की उम्मीद की जा सकती है तो हुसैन ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे (द्विपक्षीय) संबंध केवल एक मुद्दे पर अटके नहीं रहेंगे। हालांकि हुसैन ने कहा कि चूंकि हसीना अब एक घोषित अपराधी हैं, बांग्लादेश उनके जल्द से जल्द भारत से प्रत्यर्पण की उम्मीद करता है। हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। जिस दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए थे। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पांच अगस्त 2024 को उनकी सरकार का पतन हो गया। इसके बाद हसीना ने भागकर भारत में शरण ली। इस साल 17 नवंबर को एक विशेष न्यायाधिकरण ने गैरहाजिर होने पर पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युंद की सजा सुनाई गई। इससे पहले बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। ढाका में मोहम्मद यूनुस नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत भारत के साथ संबंधों के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में हुसैन ने कहा, भारत को नई वास्तविकताओं के साथ तालमेलन होने के लिए कुछ समय चाहिए। हालांकि सलाहकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहेंगे, जो दोनों पक्षों के हितों पर आधारित हों। इससे पहले बुधवार को हुसैन ने कहा था कि भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पहले की गई मांग पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ढाका अब नई दिल्ली से जवाब की उम्मीद करता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और पूर्व प्रधानमंत्री के दोषी ठहराए जाने के बाद 'स्थिति अब अलग है।

दित्वाह से श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की मौत, भारतीय एयरफोर्स 104 भारतीयों को रेस्क्यू कर लाई वापस

कोलंबो , एजेंसी। श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह से मची तबाही में अब तक कम से कम 334 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलंबिया के स्थानीय मीडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (डीएमसी) के हवाले से बताया कि 370 लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच ऑपरेशन सागरबंधु के तहत भारतीय वायु सेना श्रीलंका के आपदाग्रस्त क्षेत्रों फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। भारतीय वायुसेना ने 40 श्रीलंकाई सैनिकों और 104 भारतीयों को रेस्क्यू किया। इस तूफान से कैंडी शहर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। कैंडी में अब तक 88 मौतें हुई हैं, जबकि 150 लोग लापता बताए गए हैं। बादुल्ला में 71, नुवारा एलिया में 68 और मटाले में 23 लोगों की मौत हुई है। डेली मिरर ने डीएमसी के हवाले से बताया कि इस आपदा से देशभर के 309,607

परिवारों के 1,118,929 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय रेस्क्यू टीमें बाढ़ से प्रभावित समुदायों की मदद के लिए श्रीलंका एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, और पुलिस के साथ तालमेल बैठाकर काम कर रही हैं। वहीं फर्स्ट रिस्पांडर (जो आपदा या इमरजेंसी के समय में सबसे पहले पहुंचकर प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाते हैं) भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अन्य टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन कर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने जानकारी दी है कि श्रीलंका में फंसे 104 भारतीय नागरिकों के आखिरी बैच को सोमवार को निकालकर घर वापस लाया गया। भारतीय हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कोलंबो के बंदरनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय यात्रियों का आखिरी बैच घर पहुंच गया है। 104 फंसे हुए भारतीय आज सुबह करीब 6.30 बजे भारतीय वायु सेना के विमान से तिरुवनंतपुरम पहुंचे।' लोगों को निकालने के साथ-साथ भारत ने श्रीलंका में बचाव और राहत अभियान भी तेज कर दिए हैं। इससे पहले भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने रविवार को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका के एक प्रतिबंधित क्षेत्र से फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एक हाइब्रिड बचाव अभियान चलाया। आईएएफ ने एक्स पर कहा कि एक गरुड़ कमांडो को विंच से नीचे उतारा गया ताकि ग्रुप को कोटमाले के एक हेलीपैड तक ले जाया जा सके, जहां से 24 यात्रियों को कोलंबो पहुंचाया गया। सेना ने कहा, 'एक साथ की कोशिश में, तीन गंभीर घायलों को तुरंत मेडिकल मदद के लिए कोलंबो एयरलिफ्ट किया गया।

नक्शा विवाद के बीच नेपाल ने चीनी कंपनी को दिया नोट छपाई का ठेका, इतने करोड़ नोटों का करार

काठमांडू, एजेंसी। नेपाली नोट पर अंकित नक्शे को लेकर जारी विवाद के बीच काठमांडो ने विभिन्न मूल्यों के अपने नोटों की छपाई का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया है। 100 रुपये के नेपाली नोट पर अंकित नक्शे में भारत के तीन क्षेत्रों को अपने हिस्से में दर्शाया गया है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक (एनआरबी) के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि एनआरबी ने चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को 50, 500 व 1,000 के नेपाली रुपये के नोट छापने का ठेका दिया है। पौडेल ने कहा कि हाल में दिए गए ठेके के अनुसार चीनी प्रेस नौ महीने के भीतर नेपाली बैंक नोटों का डिजाइन, प्रिंट व आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। एनआरबी चीनी कंपनी को जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसके आधार पर वह नोट को डिजाइन करेगा। डिजाइन को एनआरबी मंजूर करेगा जिसके बाद ही नोटों की छपाई होगी।

4.30 करोड़ नोटों की छपाई के लिए हुआ करार : महीने की शुरुआत में इसी चीनी कंपनी के साथ 1,000 रुपये के 4.30 करोड़ नोटों की छपाई के लिए करार हुआ था। नेपाली रुपये के 1,000 के नोट पर दूसरी चीजों के साथ सात रोडोडेंड्रोन होंगे, जो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। नोट पर सात प्रांत दिखाए गए हैं। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को दिखाया अपना हिस्सा दरअसल, नेपाल के केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, जिसमें देश का संशोधित नक्शा छपा है। इस नक्शे में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नक्शे की निंदा की और कहा कि यह एकतरफा कृत्य है, जो जमीनी हकीकत नहीं बदलता। नक्शे को लेकर विवाद पिछले एक साल से चल रहा है और भारत ने नेपाल को आगाह किया था कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा कृत्रिम विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) की ओर से जारी नया नोट पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर वाला है। नोट पर छपाई वर्ष 2081 बीएस (साल 2024) दर्ज है। वर्ष 2020 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने संसद से मंजूरी लेकर इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। भारत का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। साल 2020 में भारत ने नेपाल के संशोधित नक्शे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एकतरफा और अस्वीकार्य कदम बताया था। नेपाल की भारत से 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।

ट्रंप लंबे समय के लिए खत्म कर सकते हैं शरण देने की प्रणाली

वॉशिंगटन, एजेंसी। बीते दिनों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद ट्रंप प्रशासन ने जांच नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं को और सख्त करने का फैसला किया है। इसके तहत अब ट्रंप की प्रशासन ने अमेरिका में आव्रजन (इमिग्रेशन) नीतियों को और कड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वे शरण देने की प्रक्रिया को लंबे समय के लिए रोकना चाहते हैं। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कई ऐसे लोग देश में आ रहे हैं जिन्हें अमेरिका में नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले अफगान नागरिक का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को अमेरिका नहीं चाहते। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है। हमारे पास पहले से ही काफी समस्याएं हैं।

व्हाइट हाउस के पास हमला : बता दें कि यह कदम उस अफगान प्रवासी की गिरफ्तारी के बाद आया है जिस पर व्हाइट हाउस के पास एक नेशनल गार्ड सदस्य की हत्या का आरोप है। बुधवार को हुए हमले में स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई, जबकि स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन ने जांच नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं को और सख्त करने का फैसला किया है।

सोमालिया जैसे देशों पर साधा निशाना : ट्रंप ने सोमालिया जैसे देशों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये ऐसे देश हैं जहां न सरकार है, न सेना, न पुलिस। लोग

एक-दूसरे को मारते रहते हैं और फिर हमारे देश आकर बताते हैं कि हमें कैसे चलाना चाहिए। हमें इनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 19 से ज्यादा देशों पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, क्योंकि वे अपराध से भरे हुए हैं। नेशनल गार्ड पर हमले का जिक्र इस दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास हुए हमले में घायल दो नेशनल गार्ड सैनिकों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एंड्रयू वोल्फ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि दूसरी सैनिक सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हमले के आरोपी अफगान नागरिक रहमनुल्लाह लाकनवाल पर योजना बनाकर और जानबूझकर की गई हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडन पर भी बोला बड़ा हमला इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना जांच-पड़ताल के लोगों को देश में आने दिया, जिससे आज यह स्थिति बनी। ट्रंप ने यह भी कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने भी कहा कि बाइडन प्रशासन ने देश के खिलाफ आत्म-नुकसान करने जैसा काम किया। गौरतलब है कि लाकनवाल 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था।

फ्लोरिडा में यूएस-यूक्रेन की मीटिंग, ट्रंप टीम जल्द मॉस्को जाकर पुतिन से करेगी वार्ता

तल्हासी, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारी रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेनी अधिकारियों से मिले, जहां प्रस्तावित शांति फ्रेमवर्क के अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बीच ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे अपने प्रतिनिधिमंडल को इस सप्ताह मॉस्को भेज रहे हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से महत्वपूर्ण वार्ता तय है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यूक्रेनी शांति दल से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब यूक्रेन एक ओर रूसी सेना से जूझ रहा है और दूसरी ओर बड़े घरेलू भ्रष्टाचार विवाद से घिरा है।

शांति समझौते के लिए अभी और काम जरूरी: रूबियो : अमेरिका और यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को लगभग चार घंटे तक बैठक की। इस वार्ता का उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रास्ता तलाशना था। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बातचीत उपयोगी रही, लेकिन अभी शांति समझौते तक पहुंचने के लिए काफी काम बाकी है। रूबियो ने कहा मुद्दा सिर्फ लड़ाई खत्म करने का नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान ढूंढना है जिससे यूक्रेन की संप्रभुता और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। आज हमने कुछ प्रगति की है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यूक्रेन की तरफ से सुरक्षा परिषद प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने हिस्सा लिया। उन्होंने अमेरिका के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा अमेरिका हमारी बात सुन रहा है, हमें समर्थन दे रहा है और हमारे साथ काम कर रहा है। उमेरोव ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि बातचीत में कितनी प्रगति हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक सुरक्षित और समृद्ध यूक्रेन है, और इस दिशा में

अमेरिका पूरी तरह सहयोग कर रहा है।

भ्रष्टाचार विवाद के बीच बदला यूक्रेन का वार्ताकार : कुछ दिन पहले राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपने शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रिय येर्माक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। ऊर्जा सेक्टर में 100 मिलियन डॉलर की गबन घोटाले की जांच के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। रूबियो की येर्माक से पिछली मुलाकात केवल एक हफ्ता पहले जिनेवा में हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने शांति योजना के संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति जताई थी।

ट्रंप-पुतिन वार्ता से पहले बढ़ी हलचल : ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ और संभवतः जेरेड कुश्नर को भेजेंगे। इस बीच, रूसी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी पुष्टि की है कि पुतिन गुरुवार से पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। ट्रंप की शांति योजना में कई विवादित बिंदु शामिल थे। जैसे यूक्रेन की सेना के आकार पर सीमा लगाने का प्रस्ताव, नाटो सदस्यता पर रोक, 100 दिनों के भीतर चुनाव करवाने की शर्त और शुरुआती प्रस्ताव में पूर्वी डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने का सुझाव, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। हालांकि, ट्रंप इस पूरी योजना को अब केवल एक 'कॉन्सेप्ट' या 'ब्लूप्रिंट' बता रहे हैं, जिससे यह साफ है कि इसके अंतिम स्वरूप को लेकर अभी भी कई पहलू तय होना बाकी हैं।

युद्ध नहीं थमा, हमले जारी : यूक्रेन में शांति वार्ता की हलचल के बीच रूस ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। शनिवार को हुए हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। वहीं, रविवार तड़के वियशहोरोड में एक आवासीय इमारत पर ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, रूस ने हाल के हमलों में 122 ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की संख्या बताते हुए कहा कि सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने 1,400 ड्रोन और 66 मिसाइलें दागीं। हमें मजबूत वायु सुरक्षा और ऐसे वास्तविक समाधान चाहिए जो युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकें।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

बस्ती में कई कारणों से दो लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए

बस्ती (एजेंसी)। विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का कार्य तेजी से चल रहा है। सोमवार को जनपद के 74.26 फीसदी मतदाताओं का डाटा डिजिटाइज्ड हो गया। अभी भी 25 फीसदी मतदाताओं का डिजिटाइजेशन का कार्य होना बाकी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 19 लाख 430 मतदाता हैं। इनमें से 14 लाख 12 हजार आठ मतदाताओं का डाटा डिजिटाइज्ड हो गया है। इनमें से 816 मतदाताओं ने खुद अपना डाटा फीड किया। एसआईआर के दौरान 48326 मतदाता ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके डाटा को बीएलओ ने परिवार वालों से कलेक्ट किया। इनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और निर्वाचक नामावली में कटे मतदाता के तौर पर डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। यह कुल मतदाताओं का 2.54 फीसदी है। जिले में 35656 मतदाता ऐसे हैं, जो अब्सेंट हैं। उनको बीएलओ खोज नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक स्थाई तौर पर 114709 मतदाता स्थाई तौर पर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। 23267 मतदाता ऐसे हैं, जो दूसरी जगह पर इनरोल्ड हैं और उनका नाम दूसरी जगह से काट दिया जाएगा। अन्य कारणों से 2777 मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। इस प्रकार कुल दो लाख 24 हजार 835 मतदाताओं का नाम सूची से हटाया है। इनका डाटा डिजिटाइज्ड कर दिया गया है।

बलरामपुर में बस-ट्रक की टक्कर, आग लगने से तीन नेपाली यात्रियों की मौत, 24 झुलसे

बलरामपुर (एजेंसी)। बलरामपुर के फुलवरिया बाईपास पर सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सोनौली से दिल्ली जा रही एक पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर हाई-टेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में तीन यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई। बस के टकराने के बाद गर्म कपड़े ले जा रहे एक ट्रक में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय बस में ज्यादातर यात्री नेपाल के थे। हादसे में 24 अन्य यात्री भी घायल हुए, जिनमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को बहराइच और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बाकी मामूली घायल यात्रियों को दिल्ली और नेपाल के लिए रवाना किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने घायलों के परिजनों से संपर्क कर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर अभी तक लापता हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन उनके खोजने में जुटे हुए हैं। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही प्रभावित परिवारों की मदद के लिए प्रशासन लगातार संपर्क बनाए हुए है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी राहत और सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

तुलसी निकेतन आवासीय परिसर का व्यापक पुनर्विकास, 20 हजार लोगों को मिलेगा आवास

गाजियाबाद (एजेंसी)। गाजियाबाद के सबसे पुराने और जर्जर हो चुके तुलसी निकेतन आवासीय परिसर का व्यापक पुनर्विकास करना, ताकि करीब 20 हजार से अधिक निवासियों को सुरक्षित और आधुनिक आवास मिल सकें। गुरुवार को जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के बीच परियोजना के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्रोजेक्ट पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पुनर्विकास की लागत न तो प्राधिकरण पर आएगी और न ही आवंटियों पर, जिससे निवासियों पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में दो चरणों में पूरा करेगा। समझौता हस्ताक्षर के बाद, आठ सप्ताह में एनबीसीसी प्राधिकरण को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें क्रियान्वयन मॉडल का आंकलन होगा। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। वर्तमान स्थिति: जीडीए ने वर्ष 1989-90 में 7.83 हेक्टेयर भूमि पर यह योजना विकसित की थी। कुल 2,292 फ्लैट (2004 ईडब्ल्यूएस और 288 एलआइजी) और 60 दुकानें बनाई गई थीं। वर्तमान में यहां 20 हजार से अधिक लोग निवास करते हैं। योजना के 16 एकड़ क्षेत्र में निजी डवलपर्स के सहयोग से नई बहुमंजिला आवासीय इमारतें बनाई जाएंगी। यह पुनर्विकास योजना तुलसी निकेतन के निवासियों को सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी... भारतीयों के एच-1बी वीजा में एक साल में ही 40 प्रतिशत की कमी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद भारतीयों के एच2-1बी वीजा में एक साल में ही 40 फीसदी की कमी आई है। यूएससीआईएस के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से अब तक एच-1बी वीजा की मंजूरी मिलने में 70 फीसदी की कमी आई है। वहीं एक साल में ही यह 37 फीसदी कम हो गया। भारत की पांच सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में टीसीएस के ही सबसे ज्यादा कर्मचारियों को एच-1बी वीजा मिला है। वहीं भारत की कंपनियों को कुल 4.5 हजार एच-1बी वीजा ही जारी हो सके हैं, जो कि इस दशक में सबसे कम हैं। टीसीएस का भी रेजेक्शन रेट 7 फीसदी तक बढ़ा है। 2024 में टीसीएस के 4 फीसदी आवेदन ही रद्द हुए थे। इस साल टीसीएस के 5293 कर्मचारियों को अमेरिका में अपनी नौकरी जारी रखने की अनुमति मिली है। वहीं भारत से अमेरिका जाने वाले कर्मचारियों को इस साल टीसीएस के केवल 846 लोगों को ही एच-1बी वीजा दिया गया है। जबकि 2024 में यह संख्या 1452 के करीब थी। अमेरिका में भारत की टॉप आईटी कंपनियों में पहले नंबर पर टीसीएस है, जिसका रिजेक्शन रेट 7 प्रतिशत है। इसके बाद इंफोसिस का रिजेक्शन रेट 1 प्रतिशत, एचसीएल अमेरिका का 1 फीसदी, एलटीआई माइंडट्री का 1 फीसदी और विप्रो का 2 फीसदी है। अमेरिका में एच-1बी वीजा के मामले में अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सबसे आगे हैं। टॉप एच-1बी वीजा पिटिशन वाली 25 कंपनियों में केवल तीन भारतीय हैं। टीसीएस के अलावा बाकी कंपनियों का रिजेक्शन रेट कम है। इसकारण कंपनियां अब आवेदन ही कम करवा रही हैं। अमेरिका में एच-1बी वीजा की नीति को लेकर एलन मस्क ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों से अमेरिका ने खूब पैसा कमाया है। मस्क ने कहा कि तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारतीय अप्रवासियों की प्रतिभा ने अमेरिका को बहुत लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों में शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं। बता दें कि बीते कुछ समय से ही ट्रंप और मस्क के रिश्तों में दरार पड़ गई है।

संचार साथी एप पर मुखर हुई प्रियंका गांधी वाड्रा... केंद्र सरकार लोगों की जासूसी करवा रहीं

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एप को मनहूस उपकरण बताया

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संचार साथी एप की विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना का जवाब देकर, विरोधी पार्टियों से संसद में व्यवधान पैदा न करने का आग्रह कर आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर बहस को तैयार है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि उन्हें मुद्दे खोदने की ज़रूरत नहीं है। कामकाज की एक सूची तैयार की गई है, और उसमें कई मुद्दे हैं। उन्हें नए मुद्दे ढूँढने और संसद को बाधित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर चिंता का अपना महत्व है, लेकिन संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उनका इस्तेमाल करना सही नहीं है। हम विपक्षी नेताओं से बातचीत करने वाले हैं, मैं पहले से ही उनके संपर्क में हूँ... हम उनके मुद्दों को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन देश में एक नहीं, कई मुद्दे हैं।

दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दूरसंचार विभाग के हालिया आदेश की आलोचना की जिसमें संचार साथी एप को जासूसी एप बताया गया है। यह हास्यास्पद है। नागरिकों को निजता का अधिकार है। हर किसी को अपने परिवार और दोस्तों को संदेश भेजने की निजता का अधिकार होना चाहिए, वे भी बिना सरकार की नज़र में आए... वे इस देश को हर रूप में तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए नहीं चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी विषय पर बात करने से मना कर रही है। विपक्ष को दोष देना बहुत आसान है। वे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं... एक स्वस्थ लोकतंत्र चर्चा की माँग करता है... धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और यह देखने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है कि भारत का हर नागरिक अपने फ़ोन पर क्या कर रहा है। इस तरह से काम नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी दूरसंचार विभाग (डीओटी) के उन निर्देशों की आलोचना की, जिसमें मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी एप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बताया गया है। उन्होंने इस निगरानी का एक मनहूस उपकरण बताया। डीओटी ने निर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एप पहली बार इस्तेमाल करते ही दिखाई दे और सुलभ हो और उस निष्क्रिय न किया जा सके। बाज़ार में पहले से मौजूद उपकरणों के लिए, कंपनियों को सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए ऐप को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है।

हैदराबाद-कुवैत इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

हैदराबाद (एजेंसी)। हैदराबाद से कुवैत जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 86 को मंगलवार सुबह बम होने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान जैसे ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा, तुरंत बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तत्काल फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया। सुबह करीब 9 बजे विमान की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग हो गई। सभी 173 यात्री और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। लैंडिंग के बाद विमान को मुंबई एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वायड, सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्ण सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है।सुरक्षा एजेंसियां धमकी भरे ईमेल की उत्पत्ति और साजिश की गहन जांच कर रही हैं। फिलहाल फ्लाइट को कुवैत के लिए रवाना करने पर फैसला जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। बता दें इससे पहले भी कई बार विमान और स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। जिसके चलते विमानों की आपात लैडिंग कराना पड़ी तो कई स्कूलों को खाली कराया गया।

तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट: तिरुवल्लूर में रेड अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

- मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया है, लेकिन इसके असर से अगले दो दिनों तक तटीय और आंतरिक जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग ने बताया कि यह निम्न दबाव क्षेत्र चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर समुद्र में केंद्रित है। इसके कारण कई जिलों में भारी वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

तिरुवल्लूर जिले में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और रानीपेट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ बहुत भारी बारिश हो सकती है। वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, विलुप्पुरम, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

3 दिसंबर को नीलगिरी, इरोड और कोयंबटूर जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, थेनी, डिंडीगुल, तिरुप्पूर, नामक्कल और सेलम जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट लागू रहेगा।

मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और तटीय क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने को कहा है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत दल तैनात कर दिए हैं। लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ है, जबकि स्कूलों को बंद रखने पर भी स्थानीय प्रशासन विचार कर रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटे राज्य के कई जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

मुस्लिम ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप दें, हिंदू भी अब कोई नया दावा पेश ना करें

-केके मुहम्मद ने की मंदिर-मस्जिद विवादों में संयम बरतने की अपील

नई दिल्ली (एजेंसी)। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने मंदिर-मस्जिद विवादों में संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि चर्चा के सेंटर में अब सिर्फ तीन जगहें- राम जन्मभूमि, मथुरा और ज्ञानवापी होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुसलमानों को अपनी मर्जी से ये जगहें सौंप देनी चाहिए। केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी कहा कि वे अब नया दावा पेश ना करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि दावों को बढ़ाने से और ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। केके मुहम्मद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मंदिर-मस्जिद विवाद से जुड़ी कई याचिकाएं देश भर की अदालतों में पेंडिंग हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केके मुहम्मद ने बताया कि राम जन्मभूमि के अलावा मथुरा और ज्ञानवापी दो और जगहें हैं जो हिंदूओं के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना हैं। अयोध्या विवाद पर बात करते हुए केके मुहम्मद ने 1976 में बीबी लाल की अगुआई में बाबरी मस्जिद की खुदाई में खुद के शामिल होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह विवाद एक कम्युनिस्ट इतिहासकार के असर की वजह से बढ़ा। उनके मुताबिक कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने मुस्लिम कम्युनिटी को इस बात के लिए मनाया कि वे मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत को खारिज कर दें। मुहम्मद के मुताबिक ज्यादातर मुसलमान शुरू में विवादित जगह पर मंदिर बनाने की इजाजत देकर मामले को सुलझाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे और खुदाई के किसी भी स्टेज पर वह उस जगह पर नहीं गए थे। उन्होंने झूठी बातें फैलाने की आलोचना की और उस समय लोगों की राय पर असर डालने वालों के बीच सीधी जानकारी की कमी की ओर इशारा किया।

मोहम्मद ने कहा है कि उस बहुत जरूरी समय में एक कम्युनिस्ट इतिहासकार ने इन सब चीजों में दखल दिया और मुस्लिम समुदाय को यकीन दिलाया कि प्रोफेसर लाल ने उस जगह की खुदाई की थी और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मंदिर के पहले से होने का पता चले। तो यह उनकी बनाई हुई चीज थी। इसलिए मुसलमानों के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि वे कभी उस जगह पर नहीं गए थे, न खुदाई से पहले, न खुदाई के दौरान और न ही खुदाई के बाद।

केके मोहम्मद ने कहा कि इसलिए बिना सब्जेक्ट जाने, कम्युनिस्ट इतिहासकार इस तरह की झूठी कहानियां फैला रहे थे। इसलिए किसी को तो इसका जवाब देना ही था। इसलिए पहली बार प्रोफेसर बीबी लाल जिन्होंने टीम को लीड किया था, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। मंदिर-मस्जिद बहस के बड़े मुद्दे पर केके मुहम्मद ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने राम जन्मभूमि के साथ-साथ मथुरा और ज्ञानवापी को हिंदू समुदाय के लिए खास महत्व वाली जगहों के तौर पर पहचाना और मुसलमानों के लिए उनकी अहमियत मक्का और मदीना जितनी बताई।

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मुसलमानों को अपनी मर्जी से ये तीन जगहें सौंप देनी चाहिए। धार्मिक जगहों से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के बारे में सवालों के जवाब में केके मुहम्मद ने कहा कि इन तीनों के अलावा हिंदू समुदाय की तरफ से कोई और मांग नहीं आनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी और दावे करने से समस्या हल नहीं होगी और आगे टकराव का खतरा रहेगा। उन्होंने ऐसी मांगों को लेकर अंदरूनी कंट्रोल की कमी पर भी कमेंट किया और कहा कि हिंदूओं के अंदर की समस्या को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने ताजमहल के बारे में कुछ हिंदू संगठनों के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्हें झूठा बताया। सांस्कृतिक विरासत के बचाव पर केके मुहम्मद ने कहा कि सरकार से जो उम्मीदें थीं खासकर उन जगहों की सुरक्षा को लेकर वे पूरी नहीं हुईं। उन्होंने मौजूदा समय को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया का काला युग बताया, और खास तरक्की न होने की आलोचना की।

डिजिटल अपराध में तेज़ी से बढ़ोतरी, सेक्सटॉर्शन और साइबर अपराध के ज़रिए मुंबईकरों से 127 करोड़ रुपये ठगे गए

मुंबई (एजेंसी)। इन दिनों मुंबई में डिजिटल अपराध में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और सेक्स्टॉर्शन एवं साइबर अपराध की वजह से मुंबईकरों से 127 करोड़ रुपये ठगे जाने की खबर सामने आई है। बताया गया है कि सेक्स्टॉर्शन के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध में शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टोकरेंसी स्कैम और प्रोविडेंट फंड स्कैम शामिल हैं। सेक्स्टॉर्शन जैसे ही साइबर अपराध जैसे डिजिटल अपराध में तेज़ी से बढ़ोतरी होने से लोगों के बीच चिंता का माहौल है। खबर है कि 2022 से अगस्त 2025 के बीच मुंबई में सेक्स्टॉर्शन के 193 और साइबर अपराध के 603 मामले दर्ज किए गए। इन डिजिटल अपराधों में लोगों से 127.6 करोड़ रुपये ठगे गए हैं। दरअसल

राज्य साइबर विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट एक्सेस और जागरूकता की कमी की वजह से सेक्सटॉर्शन और साइबर अपराध जैसे वर्चुअल क्राइम बढ़ रहे हैं। सेक्सटॉर्शन में सायबर अपराधी चैट या वॉट्सअप ऐप वीडियो कॉल के दौरान मॉर्फ्ड, आपत्तिजनक इमेज दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठे जा सकें। इस बीच, साइबर अपराध में अपराधी सोशल मीडिया पर लोगों को टारगेट करते हैं और अपनी असली पहचान छिपाते हैं। मुंबई के पवई इलाके में रहने वाले एक युवा मैनेजर ने क्वेक ब्वाक डी नाम के डेटिंग ऐप पर दिव्या नाम की एक महिला से दोस्ती की। 20,000 रुपये चार्ज करने के बाद, दिव्या ने पीड़ित का निजी वीडियो उसके भाई, दोस्तों और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के सदस्यों को भेज दिया। फिर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट न करने का वादा करके मैनेजर से 2 लाख रुपये ऐंठ लिए। इस बीच, मलाड की एक छात्रा को छह महीने तक साइबर अपराध का सामना करना पड़ा। जब पुलिस ने मुंबई से सटे मीरा रोड से आफताब को गिरफ्तार किया, तो उन्हें पता चला कि पीड़िता उसे कॉलेज में इग्नोर कर रही थी। इसीलिए वह उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे परेशान कर रहा था।

क्या हम उनके लिए लाल कालीन बिछाएं? रोहिंग्या घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीमित कल्याणकारी संसाधनों पर दबाव पर ज़ोर देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपके गरीब बच्चे इन लाभों के हकदार नहीं हैं? क्या हमें कानून को इतना ज़्यादा खींचना होगा? पीठ ने अवैध प्रवासन, खासकर भारत की उत्तरी सीमाओं पर, से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर भी प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे के राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू पर ज़ोर देते हुए कहा कि उत्तर भारत में हमारी सीमा बेहद संवेदनशील है। अगर कोई घुसपैठिया अवैध रूप से प्रवेश करता है, तो क्या उसे यहीं रखना हमारा दायित्व है? ये टिप्पणियाँ रोहिंग्याओं के लापता होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान आईं।

हालाँकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका के मूल आधार पर ही सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि यह याचिका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जिसका ऐसे मुद्दे उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जनहित याचिका याचिकाकर्ता, जिसका रोहिंग्याओं से कोई लेना-देना नहीं है, ये प्रार्थनाएँ कर रहा है। अदालत से इस याचिका पर विचार न करने का आग्रह किया। पक्षों की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि वह 16 दिसंबर को इस पर फिर से विचार करेगी। ये टिप्पणियाँ रोहिंग्य ओं के लापता होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान आईं। हालाँकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका के मूल आधार पर ही सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि यह याचिका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जिसका ऐसे मुद्दे उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जनहित याचिका याचिकाकर्ता, जिसका रोहिंग्याओं से कोई लेना-देना नहीं है, ये प्रार्थनाएँ कर रहा है,÷ और अदालत से इस याचिका पर विचार न करने का आग्रह किया। पक्षों की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि वह 16 दिसंबर को इस पर फिर से विचार करेगी।

कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके के बीच समझौता... तूफान के आने से पहले की शांति

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के विपक्षी दलों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कर्नाटक के नाटक को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बीच 'समझौता' अस्थायी है। उन्होंने कहा, यह तूफान से पहले की शांति और एक 'रणनीतिक समायोजन' है। लेकिन कांग्रेस ने मुद्दे पर भ्रम पैदा करने के लिए विपक्ष और मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। एक महीने से चल रहे सत्ता संघर्ष के बाद दोनों नेताओं ने शनिवार को सिद्धरमैया के आवास पर नाश्ते पर मुलाकात कर मतभेदों के दूर होने की बात कही। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने बाद में प्रेसवार्ता को संबोधित किया, एकता का प्रदर्शन कर ऐलान किया कि वे पार्टी आलाकमान का कहना मानने वाले है। इस तरह, उन्होंने मुख्यमंत्री परिवर्तन पर विवाद को खत्म करने की कोशिश की। कथित तौर पर 2023 में कर्नाटक में सरकार बनाते समय सहमति बनी थी कि ढाई साल के कार्यकाल के बाद शिवकुमार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने हैं, और ढाई साल नवंबर 2025 में पूरे हुए।

राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रकाश शेषराघवचार के मुताबिक जिस बैठक के परिणामस्वरूप संघर्ष विराम हुआ, वह ''हर असहमति को सुलझाने के बारे में कम और कामकाजी सद्भाव को बहाल करने के बारे में अधिक थी''। उन्होंने दावा किया, ''यह केवल एक अस्थायी समझौता है। एक बार जब कोई राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होता है, तब आप उस शख्स को कुछ समय के लिए शांत करा सकते हैं, लेकिन यह फिर से उभरेगा।' बीजेपी नेता शेषराघवचार के मुताबिक, शिवकुमार ने अपने समर्थकों को उनके पक्ष में आवाज उठाने के लिए उकसाया था। इसके बाद ''शिवकुमार के समर्थक विधायक दिल्ली गए और कुछ संत भी उनके समर्थन में आए। अब डीके पीछे नहीं हट सकते। इस बात से उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है, जिसे उन्होंने खुद न्यौता दिया है। हो सकता है कि मीडिया या किसी और माध्यम से इस नए सिरे से शुरू करने के लिए वह कुछ समय तक चुप रहें।''

भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस अब दो गुटों में बंट चुकी है और इसकी लड़ाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जैसी हो गई है, जहां गुटबाजी ने चुनाव में इसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। अन्य विपक्षी पार्टी जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के विधान पार्षद (एमएलसी) टी ए शरवण ने बताया कि इस विवाद ने दोनों नेताओं और उनकी पार्टी को जनता के सामने पहले ही बेनकाब किया है, लेकिन अब वे अपने झगड़े को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ''राज्य के लोग एकता के इस प्रदर्शन को स्वीकार नहीं करने वाले है। कर्नाटक सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थ है और विकास कार्यों को करने में विफल रही है। इसलिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नाटक का मंचन किया।''

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामकृष्ण उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सिर्फ सुलह-समझौते का काम किया है, जो ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। उन्होंने कहा, ''कल की नाश्ते पर बैठक आलाकमान के आदेश पर हुई थी, इस उन्होंने (मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने) स्वेच्छा से नहीं किया था। उनके बीच पहले से ही मतभेद थे। नाश्ते पर बैठक और प्रेसवार्ता आलाकमान द्वारा पूरी तरह से सुनियोजित कदम था। वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय ने कहा, ''सिद्धरमैया और शिवकुमार ने ठीक वहीं किया, जो उन्हें बताया गया था, कि वे साथ हैं, उनमें एकता है, उनके बीच कोई मतभेद नहीं हैं और वे कांग्रेस आलाकमान की बातों पर अड़े रहने वाले है। लेकिन इतने महीनों और पिछले एक हफ्ते से चल रही तीखी खींचतान के बाद, क्या समाधान की कोई संभावना है? नतीजा शून्य है।''

उनके अनुसार, नाश्ते की बैठक में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्पष्टता का अभाव था कि क्या आलाकमान ने डीके को मुख्यमंत्री बनाने के संबंध में कोई वादा किया था। कांग्रेस प्रवक्ता एम. लक्ष्मण ने जोर देकर कहा कि दोनों नेताओं के बीच किसी भी समय कोई मतभेद नहीं था। लक्ष्मण ने बताया कि ''मतभेदों का विमर्श भाजपा और जनता दल (एस) और मीडिया के एक वर्ग का नतीजा है। अगर कोई समझौता हुआ था, तब वह कांग्रेस का अंदरूनी मामला था और फैसले पार्टी को लेने थे।